

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

भारत में, कोविड -19 की घटनाओं में कमी आने के कारण आर्थिक गतिविधियाँ तेज हो रही हैं और टीकाकरण के आरंभ होने से उम्मीद जागी है। कुल मांग में भी तेजी आई है ; केवल निजी निवेश न के बराबर है और इसके पुनः आरंभ होने के लिए समय उपयुक्त है। चलनिधि के व्यापक उपाय प्रणाली में मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों के आसान होने को दर्शाते हैं।

समय की पटरियों पर एक दौड़ जारी है - संक्रमण बनाम इंजेक्शन; टीकाकरण बनाम म्यूटेशन। अब तक, पौराणिक ग्रीस की शिकारी एटलांटा की तरह, जिसकी शर्त यह थी कि वह उससे शादी करेगी जो उससे आगे निकाल जाएगा लेकिन जिनसे वह आगे निकाल जाएगी उन्हें वह मार देगी, उसी तरह से अभी संक्रमण आगे चल रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कोरोनोवायरस रिसोर्स सेंटर के अनुसार, फरवरी 2021 के अंत तक, वैश्विक संक्रमण 192 देशों में 114 मिलियन पर बंद हो गया। फिर भी, इंजेक्शन की दिशा में बेहतर काम हो रहा है। कुल मिलाकर, दुनिया भर के 64 देशों में 50 मिलियन से अधिक लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। टीकाकरण की गति में वृद्धि जारी है, लगभग 6.17 मिलियन खुराक एक दिन में (ब्लूमबर्ग)। बुरी खबर यह है कि, कोविड -19 म्यूटेशन जो संभवतः टीकों द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी के आंशिक प्रतिरोध को स्वीकार करता है, अब अमेरिका में है, जो लगातार बदलते हुए वायरस से लड़ने के नए तरीकों की जांच के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित कर रहा है और जो वर्षों तक सक्रिय रह सकता है। दक्षिण अफ्रीकी संस्करण पहले से ही अफ्रीकी महाद्वीप में तेजी से फैल गया है और अफ्रीका के बाहर कम से कम 24 देशों में देखा गया है। 29 दिसंबर, 2020 को पहली बार कोलोराडो में देखा गया यूके म्यूटेशन एक महीने से भी कम समय में 29 अमेरिकी राज्यों में पाया गया था। दोनों प्रकारों को मूल स्ट्रेन से अधिक संक्रामक माना जाता है। टीकों के संबंध में लेट-स्टेज ट्रायल्स प्रभावकारिता में एक असमान गिरावट

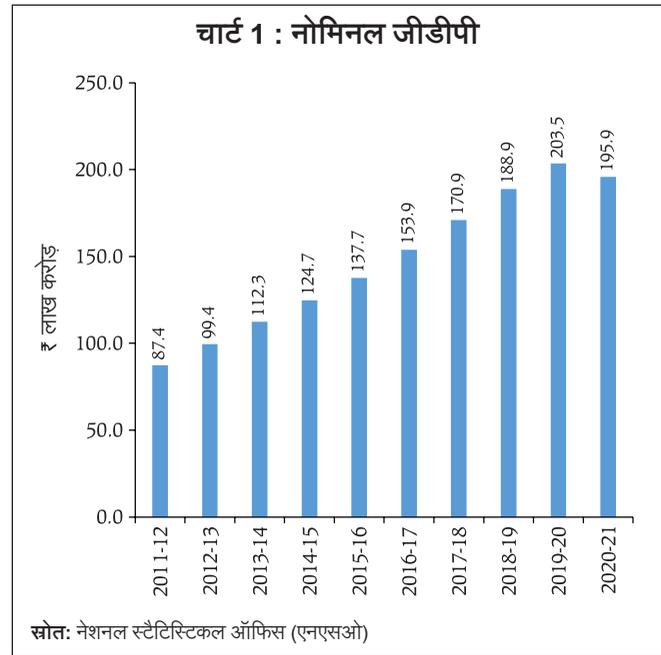
* यह लेख माइकल देवव्रत पात्रा, कुणाल प्रियदर्शी, शशिधर एम.लोकरे, कृष्ण मोहन कुशवाहा, के.एम. नीलिमा, अभिनंदन बोरड़, जितेंद्र सोकल, मनु शर्मा, शोभित गोयल, बरखा गुप्ता, सक्षम सूद, प्रियंका सचदेवा, ऋषभ कुमार, ऋवेन यंगरोल, राजस सरोय, शाहबाज खान, अशीष थॉमस जॉर्ज, देबा प्रसाद रथ, प्रज्ञा दास और समीर रंजन बहेरा। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

को दर्शाता है। टीके बनाने वालों को अब बूस्टर शॉट या नए एडजस्टेड वैक्सीन पर काम करने के लिए गियर्स को मिड-कोर्स में शिफ्ट करना होगा जो म्यूटेशन के खिलाफ बेहतर काम कर सकते हैं। यह तेजी से काम करने के लिए उकसाने वाला समय है: वायरस म्यूटेट होगा और हमें चुनौती देगा - 100 मिलियन से अधिक संक्रमित लोग होने के कारण, उत्परिवर्तन के लिए 100 मिलियन संभावनाएं हैं।

भारत कम से कम तीन महत्वपूर्ण तरीकों से अनजान मार्ग को अपना रहा है। सबसे पहले, कोविड -19 रोगियों की बढ़ती संख्या, जो सितंबर 2020 में अपने चरम पर पहुँच कर प्रतिदिन 1,00,000 नए पुष्टि किए गए संक्रमणों पर आ गई थी वह फरवरी 2021 में कम हो कर दिन में लगभग 12,500 औसत पर आ गई जिसके चलते डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य फ्रंटलाइन वारियर्स को एक अप्रत्याशित राहत मिली। स्वास्थ्य सर्वेक्षणों से अब पता चलता है कि वायरस का एक्सपोजर पहले की तुलना में बहुत अधिक था, जिससे यह देखने को मिला कि भारत के भीड़-भाड़ वाले शहर और कस्बे टीके की उपलब्धता से पहले ही हर्ड इम्यूनिटी के शुरुआती चरणों में हो सकते हैं। या कम से कम यह उम्मीद है कि सबसे खराब समय खत्म हो गया है, इस लेख¹ के दिसंबर 2020 के अंक में किए गए पूर्वानुमान की पुष्टि करता है। युवा हमारे पक्ष में हैं - लगभग 95 प्रतिशत आबादी 65 वर्ष से कम आयु की है। इसके अलावा, भारत ने यह पहले भी किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में लक्षणहीन संक्रमणों के उच्च अनुपात का कारण है अन्य पैथोजन के पूर्व संपर्क में आना ; पोलियो और खसरा के खिलाफ हमारी लड़ाई हमारे महत्वाकांक्षी टीकाकरण अभियान में बेहतर है, जिसका लक्ष्य अगस्त के अंत तक 300 मिलियन का टीकाकरण करना है। 500,000 के लक्ष्य (21 दिन) तक पहुंचने के लिए सबसे तेज पहुंचने के कारण भारत केवल डेलीवर की गई वैक्सीन की खुराक के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन से पीछे है। 16 जनवरी को ही अपना टीकाकरण अभियान शुरू करने के बावजूद, भारत दुनिया के 70 प्रतिशत टीकों की आपूर्ति के लिए अपनी दवा निर्माण क्षमता का उपयोग कर रहा है, अब तक 15 देशों में आपूर्ति की गई है और अन्य 25 देश कतार में हैं, जिनमें पड़ोसियों को दान भी शामिल है - एक शान्तिप्रिय शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन।

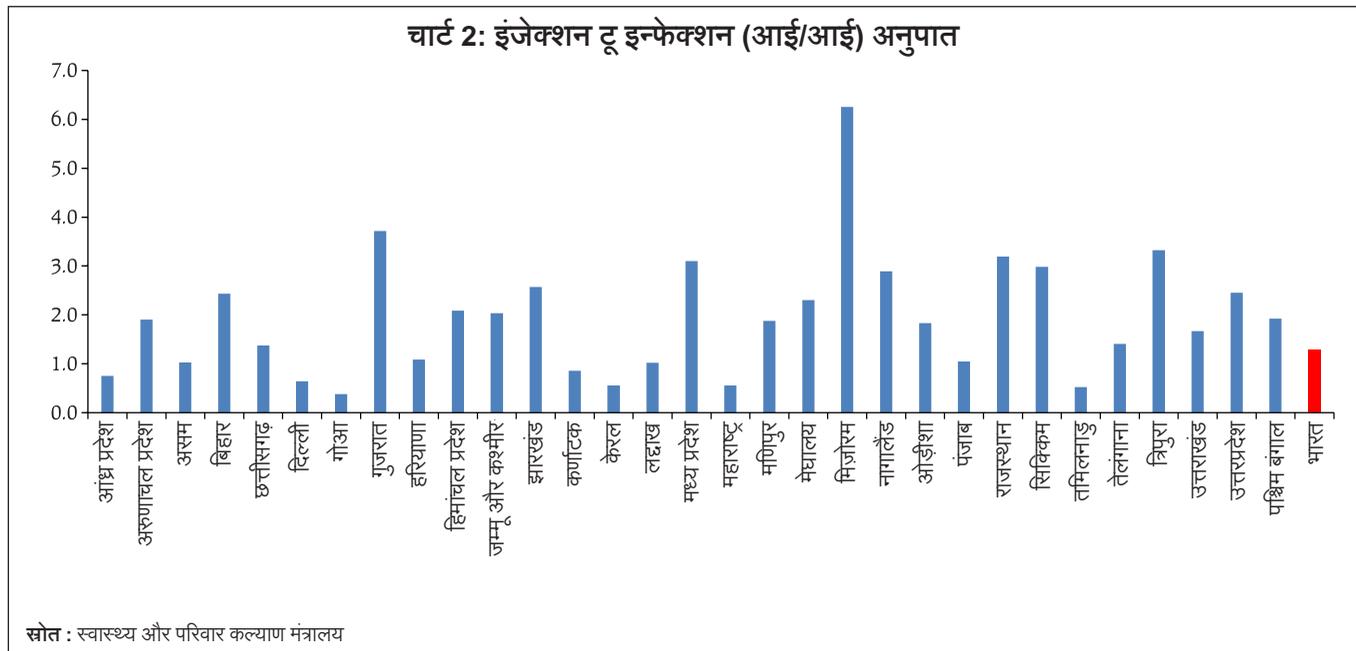
¹ 30 जनवरी, 2021 के फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पर ध्यान दिया, क्योंकि 'ईबुलेंस' ऑफ दी 'नोर्मली स्टेड भारतीय रिजर्व बैंक'

नाममात्र जीडीपी के संदर्भ में, 96 प्रतिशत पूर्व-महामारी आर्थिक गतिविधि को बहाल किया गया है, यह मानते हुए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का पहला अग्रिम अनुमान अभी भी लागू है (चार्ट 1)। Q3 के लिए प्रारंभिक कॉर्पोरेट परिणाम: 2020-21 यह दर्शाता है कि बिक्री में सुधार जारी है क्योंकि वे संकुचन से बाहर निकले हैं; कच्चे माल की लागत में गिरावट और कम ब्याज खर्च के कारण बचत के साथ संयुक्त रूप से परिचालन लाभ में उछाल आया है। गैर-वित्तीय क्षेत्र में प्रो-साइक्लिकल उद्योगों - ऑटो, स्टील और सीमेंट - ने वॉल्यूम में तेज पलटाव दर्ज किया, एक मजबूत मूल्य निर्धारण वातावरण में उत्पादन की कीमतों में वृद्धि और लागत में कटौती के उपायों को अपनाया। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र ने स्पष्ट रूप से महामारी-प्रूफिंग का प्रदर्शन किया है, कई वर्षों में इसकी सबसे मजबूत तिमाही बिक्री में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, आईटी की प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर की कीमतों ने बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बनने के लिए एक्सचेंज को पीछे छोड़ दिया। दूसरी ओर, तिमाही के दौरान तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी) और दवा कंपनियों की बिक्री वृद्धि ने मुनाफे में वृद्धि को दर्शाया। पूरे भारत में, और अधिक बच्चों को स्कूल जाना है, अधिक श्रमिकों पेशेवरों को अपने कार्यस्थलों पर, और बुजुर्गों को बाहर जाना है। संक्रमण और इंजेक्शन के



बीच में (1 से 1) अनुपात दिखाता है (चार्ट 2), अभी एक लंबी और कठिन यात्रा तय करनी है और बही संतुष्ट होने की कोई जरूरत नहीं है।

दूसरा, भारत में नीति निर्माता प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसर में बदलने के लिए वायरस से पहल कर रहे हैं। 1 फरवरी, 2021 को वित्त मंत्री ने "विश्वास और आशा" के भारत के बजट का



अनावरण किया। मितव्ययिता को न कहते हुए, केंद्रीय बजट पारदर्शिता और व्यावहारिक विवेक के साथ साहस और आशावाद को संतुलित करने के लिए इतिहास में याद रखा जाएगा। कोई नया कर नहीं, अनुपालन में आसानी और, वास्तव में, अनुपालन से कर उछाल, ऋण की कमी से निपटने के नए तरीके और फिर भी सबसे बड़े पूंजीगत परिव्यय के साथ 5.54 लाख करोड़, यह एक दुर्लभ प्रतिक्रिया में आश्चर्य की बात नहीं है, वित्तीय बाजारों ने एक बजट बनाया। वाहवाह! जैसा कि अरस्तू ने 350 ईसा पूर्व में अपनी पोलिटिका में लिखा था, "अच्छी तरह से शुरुआत मतलब आधा काम हो गया।"

तीसरा, राजकोषीय नीति में वृद्धि के प्रति व्यय के साथ, लेकिन एक लिफाफे के भीतर, जो महामारी उधारों के विंड-डाउन की भी परिकल्पना करता है - सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) को जीडीपी के 9.5 प्रतिशत से नीचे 6.8% तक जाने के लिए बजट दिया जाता है - मौद्रिक नीति वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक घोषणा में अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा बन गई। यह देखते हुए कि दिसंबर में महंगाई में कमी ने विकास को समर्थन देने की गुंजाइश प्रदान की, मौद्रिक नीति समिति ने 5 फरवरी को नीतिगत दर को अपरिवर्तित छोड़ दिया और चालू वित्त वर्ष के माध्यम से और अगले में अपने समय के आकस्मिक रुख को बनाए रखा। भाग्य बहादुर के पक्ष में होता है - जनवरी 2021 के प्रिंट में, मुद्रास्फीति 4.06 प्रतिशत पर आ गई, नीचे के रास्ते पर लक्ष्य के सिर्फ 6 आधार अंक कमा उसी समय, रिज़र्व बैंक ने समाज के सभी सदस्यों के लिए केंद्र सरकार के उधार कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए सभी कार्य आरंभ किए, उपज वक्र के क्रमिक विकास की प्रतिपूर्ति और वित्तीय स्थिरता को गैर-प्रतिद्वंद्विता और उपयोग के लिए बाहर न रखने योग्य बताया। इसने गिल्ट मार्केट में एक नया और सबसे भरोसेमंद निवेशक - भारतीय सेवर, आम आदमी - लाया, जो अब रिज़र्व बैंक के साथ ही गिल्ट सिक्योरिटीज अकाउंट है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय परिवार 2019-20 में शेष अर्थव्यवस्था का एकमात्र ऋणदाता था, जिसके लिए नवीनतम वर्ष पूरी जानकारी उपलब्ध है। दूसरा, इसने बैंकों द्वारा खरीदी गई नई प्रतिभूतियों की

परिपक्वता के लिए धारण का विस्तार किया। नतीजतन रुपये 4 लाख करोड़ के स्तर तक प्रतिभूतियों की होल्डिंग ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से अछूता रहेगा और इसलिए बैंकों को 'मार्क-टू-मार्केट' नुकसान से बचाया जाएगा। तीसरा, पहली बार रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने चलनिधि पर आगे मार्गदर्शन प्रदान किया और कहा कि इस पर ध्यान आकर्षित करना सार्थक है:

"मौद्रिक नीति के रुख के साथ चलनिधि प्रबंधन का रुख लगातार और पूरी तरह से मेल खाता है। आरबीआई प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार ट्रैक्शन प्राप्त करने के लिए वसूली के लिए अनुकूल वित्तीय स्थितियों को बढ़ावा देता है। सीआरआर सामान्यीकरण अतिरिक्त चलनिधि को इंजेक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के बाजार संचालन के लिए स्थान खोलता है। इन क्षेत्रों में हमारे प्रयास का अंतर्निहित विषय वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाले बिना उचित रूप से हमारे पास उपलब्ध सभी लिखतों का लचीले ढंग से उपयोग करना होगा, जो कि आरबीआई के नीतिगत उद्देश्यों के मूल में है। सरकार के ऋण प्रबंधक और बैंकर के रूप में, रिज़र्व बैंक बिना किसी व्यवधान के बाजार उधार कार्यक्रम को पूरा करना सुनिश्चित करेगा। इस संदर्भ में, हम बाजार के खिलाड़ियों और आरबीआई के बीच आम समझ और सहकारी दृष्टिकोण की निरंतरता के लिए तत्पर हैं..."

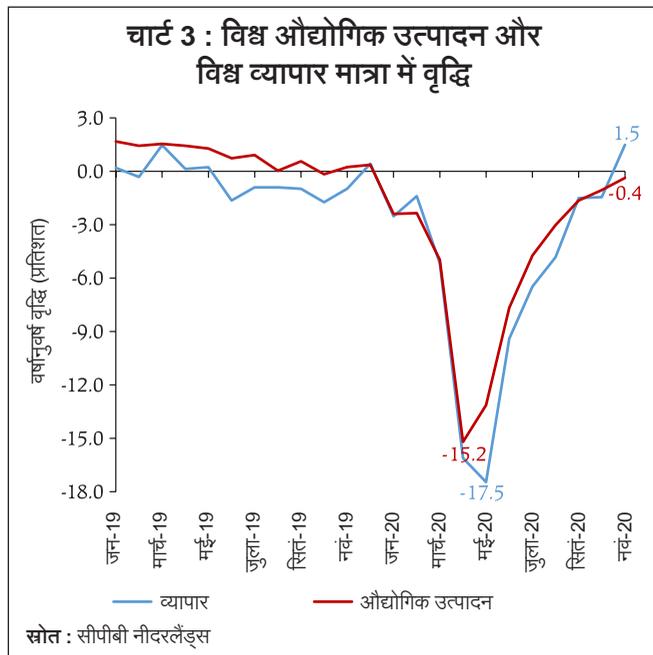
दिया गया संदेश असंदिग्ध है: चलनिधि पर्याप्त बनी रहेगी [25 फरवरी, 2021 को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत कुल अवशोषण रुपये 7.1 लाख करोड़ था]; रिज़र्व बैंक पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करेगा (19 फरवरी 2021 तक, रिज़र्व बैंक ने रु. 3.0 लाख करोड़ की खुली बाजार खरीद का संचालन किया है जबकि विदेशी मुद्रा संचालन ने 2020-21 में घरेलू चलनिधि रु. 5.4 लाख करोड़ तक बढ़ाई थी)। रिज़र्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के सामान्यीकरण के माध्यम से वापस ली गई चलनिधि को लगभग रु. 1.6 लाख करोड़ के बराबर कर देगा; और रिज़र्व बैंक एक क्रमबद्ध तरीके से सरकार के उधार कार्यक्रम को पूरा करेगा। अफ़सोस की बात है कि ये संदेश कुछ बांड व्यापारियों द्वारा खो गए थे! रिज़र्व बैंक की

घोषणाओं का उद्देश्य दुनिया को परिवर्तित करना नहीं था, लेकिन हम जो हैं, हम हैं – सभी निर्भीक लोग और एक समान स्वभाव²।

II. ग्लोबल सेटिंग

ति.3: 2020 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में एक मजबूत पलटाव, छुपी हुई खपत की मांग और कार्यालय से दूर रहकर कार्य करने में समायोजन द्वारा संचालित, ति. 4 में दूसरी / तीसरी लहरों के संक्रमण के बाद बंद, विशेष रूप से नए और अधिक संक्रामक स्ट्रेन और सख्त लॉकडाउन का माहौल आया (चार्ट 3)।

वैक्सीन की मंजूरी, कुछ देशों में अतिरिक्त नीति प्रोत्साहन के टीकाकरण और घोषणाओं का शुभारंभ इस उम्मीद को बल देता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था Q1 के करीब और Q2 में गति प्राप्त करेगी। इसने 2021 के लिए दृष्टिकोण को उज्ज्वल किया है। 2021-22 के दौरान अधिकांश देशों में टीके की उपलब्धता की धारणा पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने जनवरी 2021 के अपडेट में वैश्विक जीडीपी अनुमानों को 2021 से 5.5 प्रतिशत तक संशोधित किया है। अक्टूबर रिलीज़ (तालिका 1) में अनुमानित 5.2 प्रतिशत से विश्व आर्थिक



आउटलुक (डबल्यूईओ)। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) को वैक्सीन खुराक और अतिरिक्त नीति समर्थन के स्टॉकपिलिंग से एक बढ़त हासिल करने की संभावना है, जिसमें व्यापारिक साझेदारों के लिए अनुकूल स्पिलओवर और उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए जोखिम प्रवाह तेज है। इसलिए, रिकवरी की ताकत और गति, पूरे देशों में असमान और भिन्न बने रहने की उम्मीद कर सकती है। इस संदर्भ में एक भयावह नोट पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने संकेत दिया है कि यदि वैक्सीन की देरी के कारण विकासशील देशों में महामारी फैलती रहती है और यदि टीका वितरण असमान है, तो यह 4.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का क्षरण कर सकता है। विश्व उत्पादन में 2021 में या पूर्व-महामारी वैश्विक आउटपुट 3 का लगभग 5.7

तालिका 1 : जीडीपी वृद्धि अनुमान – चुनिन्दा ईई और ईएमई

(वर्षानुवर्ष, प्रतिशत)

देश	2020		2021	
	अक्टू 2020	जन 2021	अक्टू 2020	जन 2021
विश्व	-4.4	-3.5	5.2	5.5
विकसित अर्थव्यवस्थाएँ				
यूएस	-4.3	-3.4	3.1	5.1
यूरो एरिया	-8.3	-7.2	5.2	4.2
यूके	-9.8	-10.0	5.9	4.5
जापान	-5.3	-5.1	2.3	3.1
उदयमान मार्केट अर्थव्यवस्थाएँ				
ब्राज़ील	-5.8	-4.5	2.8	3.6
रूस	-4.1	-3.6	2.8	3.0
भारत	-10.3	-8.0	8.8	11.5
चीन	1.9	2.3	8.2	8.1
साउथ अफ्रीका	-8.0	-7.5	3.0	2.8

स्रोत : विश्व बैंक

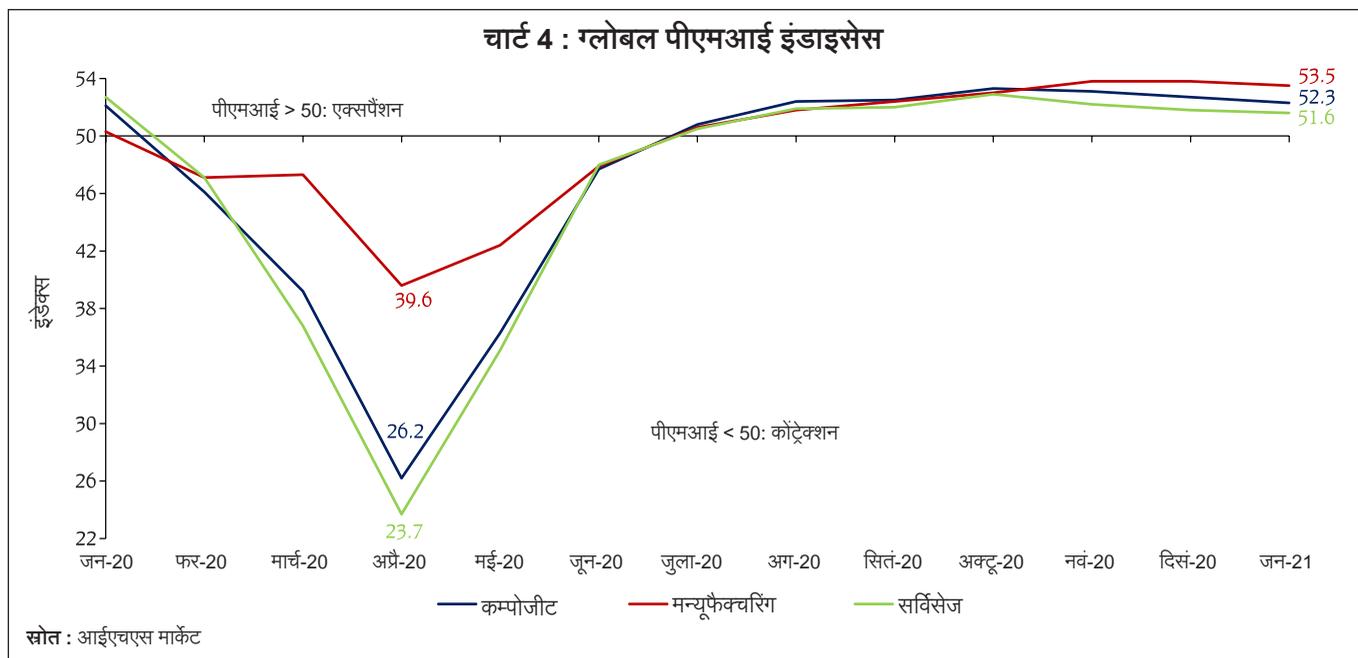
² लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन अपनी कविता यूलिसिस से।

प्रतिशत। एई को इस नुकसान का खामियाजा भुगतने की उम्मीद है: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापारिक गतिविधियों में परिणामी व्यवधान के परिणामस्वरूप महामारी का यूएस \$ 2.4 ट्रिलियन या 3.5 प्रतिशत वार्षिक नुकसान हो सकता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट (जीएफएसआर) के आईएमएफ के जनवरी 2021 के अपडेट से यह अनुमान भी लगता है - टीकों की असमान पहुंच वित्तीय अस्थिरता के जोखिमों को बढ़ा सकती है।

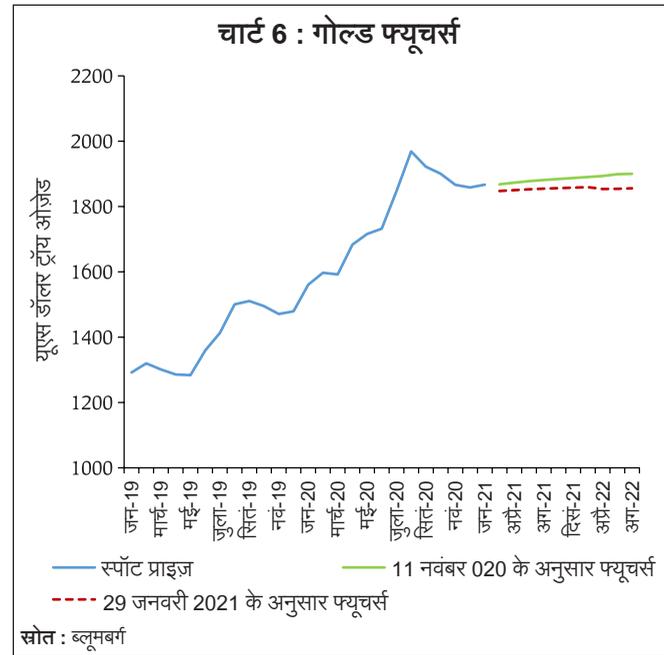
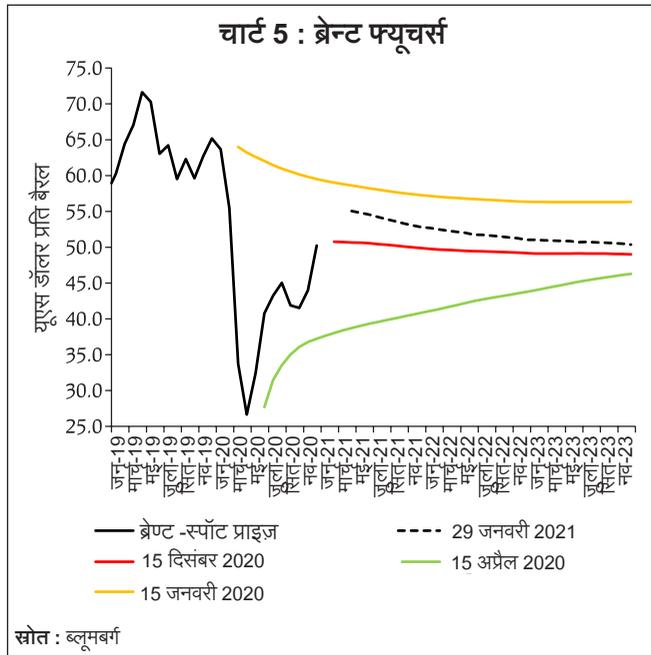
वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जनवरी 2021 में लगातार तीसरे महीने में कम हुआ क्योंकि विनिर्माण और सेवा गतिविधि दोनों ने वर्ष की शुरुआत में (चार्ट 4) गति खो दिया था। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई 53.5 के तीन महीने के निचले स्तर पर गिर गया, जबकि पीएमआई सेवाओं के छह महीने के निचले स्तर 51.6 पर पहुंच गया, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि और नए आदेश नए निर्यात आदेशों के साथ-साथ गतिरोध में फिसल गए। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं गंभीर रूप से फैली हुई हैं, जिसमें वेंडर लीड समय पीएमआई सर्वेक्षण के इतिहास में सबसे अधिक

है। आपूर्ति की गड़बड़ी के मद्देनजर, खरीद मूल्य में वृद्धि हुई है, जैसा कि उच्च उत्पादन शुल्क में प्रकट होता है, जबकि इनपुट मूल्य दबाव का निर्माण जारी है।

प्रोत्साहन घोषणाओं और वैक्सीन रोलआउट के द्वारा 2021 की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही। अमेरिका में गिरते कच्चे तेल की सूची के बीच आपूर्ति में और अधिक वृद्धि हुई है। फरवरी और मार्च में प्रति दिन 1 मिलियन बैरल से उत्पादन में कटौती की, सऊदी अरब की घोषणा ने दोनों भावनाओं और कीमतों को हटा दिया - जनवरी में औसतन \$ 54.5 प्रति बैरल, ब्रेंट क्रूड जनवरी (चार्ट 5) में 9.4 प्रतिशत महंगा था। इसके अलावा, कच्चे तेल का वायदा दिसंबर 2020 के बाद से पिछड़ेपन में चला गया, जो कच्चे तेल के बाजार में मजबूती को दर्शाता है। वर्ष की दूसरी छमाही में मांग में पर्याप्त सुधार की उम्मीद है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के साथ-साथ भारी माल की आपूर्ति में कटौती से ऐसे परिदृश्य में गिरावट आ रही है जहां शेल उत्पादन की प्रतिक्रिया म्यूट रहने की संभावना है, कीमतों को बनाए रख रहे हैं।



³ <https://www.ft.com/content/53c668bc-1066-4d8c-8c8d-5d29ba34a06e>.



सोने ने 2021 में अपनी जीत की लकीर को खो दिया, जिसमें 2.7 प्रतिशत (चार्ट 6) की कीमतों में सुधार हुआ। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने, अमेरिकी बॉन्ड की पैदावार में वृद्धि और मजबूत जोखिम की भावनाओं ने पीली धातु की चमक को कम कर दिया है। दूसरी ओर, चीन की फैक्ट्री गतिविधि में रिकवरी और ट्रैक्शन, जैसा कि वैश्विक विनिर्माण पीएमआई में दिखाया गया है, ने आधार धातुओं की कीमतों को बढ़ावा दिया है।

व्यापार मोर्चे पर, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 2021 को जारी नवीनतम रिपोर्ट ने ति.3: 2020 में वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के व्यापार में 24 प्रतिशत सालाना (वर्षानुवर्ष) में संकुचन की सूचना दी, जिसमें पिछली तिमाही में 30 प्रतिशत से गिरावट आई है। माल व्यापार में गिरावट अपेक्षाकृत मध्यम थी - 5.6 प्रतिशत। सेवाओं के व्यापार में मंदी नवंबर के अनुमान के अनुसार प्रारंभिक अनुमान के अनुसार जारी रहने की उम्मीद है। अधिकांश उप-क्षेत्र संकुचन क्षेत्र में बने हुए हैं, जिसमें यात्रा क्षेत्र को ति.3: 2020 में वैश्विक स्तर पर 68 प्रतिशत की गिरावट आई है। दूसरी ओर, गुड्स ट्रेड ने नवंबर, 2020 में मूल्य में क्रमिक सुधार को अपने 2019 स्तरों की तुलना में 4 प्रतिशत बढ़ा दिया। दो कारकों ने मुख्य रूप से इस वसूली को सहायता प्रदान की है, वर्ष के शुरुआती हिस्से में खरीद को स्थगित कर दिया और एक अनुकूल आधार प्रभाव।

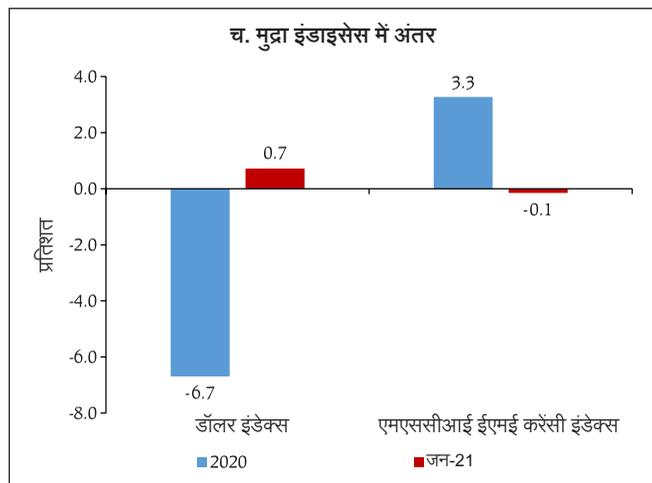
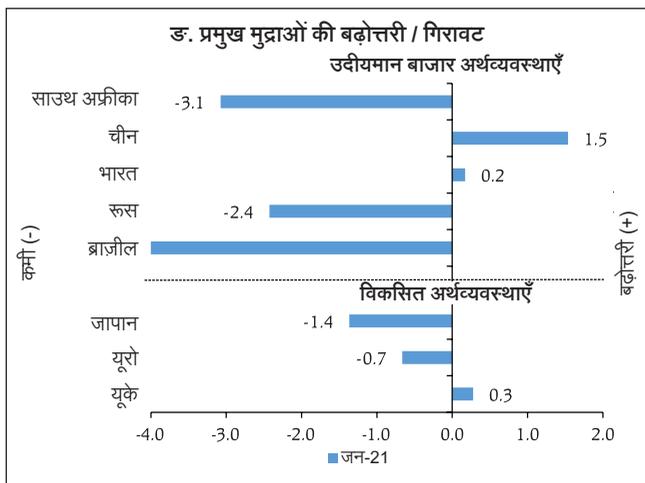
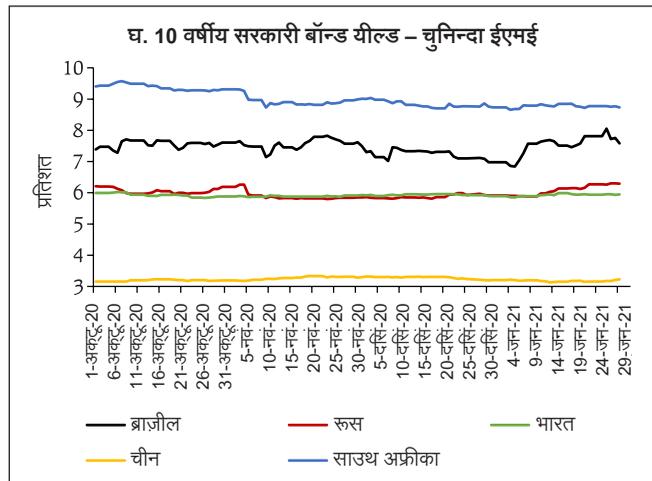
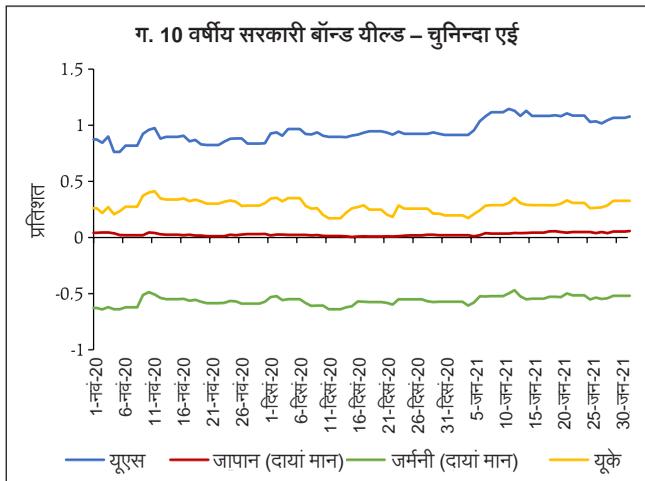
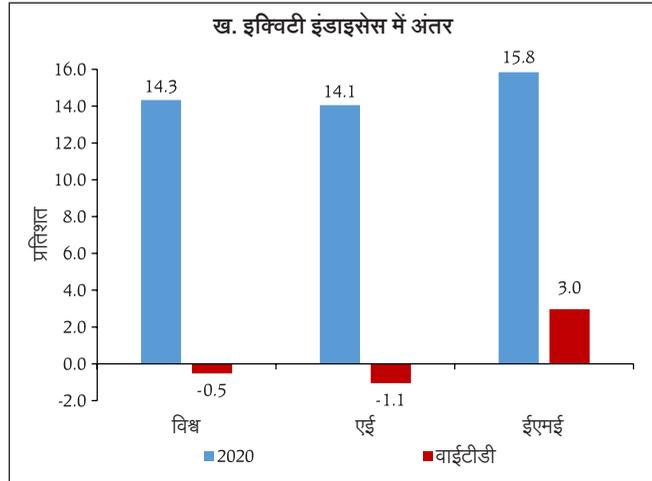
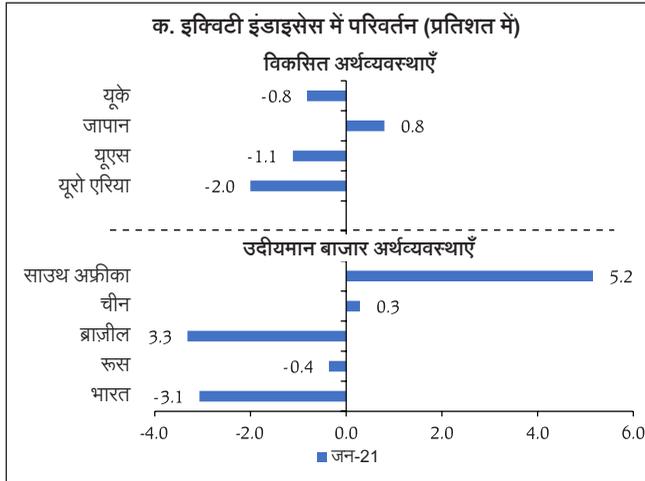
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निवेश रुझान मॉनिटर के अनुसार, वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) ने 2020 तक यूएस \$ 1.5 ट्रिलियन से 2020 तक अनुमानित रूप से \$ 859 बिलियन के मुकाबले 42 प्रतिशत की गिरावट के साथ, एक प्राथमिक गिरावट दर्ज की। (यूएनसीटीएडी) 24 जनवरी, 2021 को जारी किया गया। विभिन्न प्रभाव दिखाई दे रहे थे क्योंकि विकसित देश सबसे कठिन प्रभाव में बने रहे, प्रवाह में 69 प्रतिशत की गिरावट के साथ अनुमानित अमेरिकी \$ 229 बिलियन, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 12 प्रतिशत की अधिक मध्यम यूएस \$ 616 बिलियन प्रतिधारण देखी गई। 2021 में वायरस के दौरान लगातार अनिश्चितता के कारण गिरावट के बावजूद, विकासशील देशों में एफडीआई प्रवाह कुल वैश्विक एफडीआई प्रवाह का 72 प्रतिशत है - रिकॉर्ड पर सबसे अधिक हिस्सेदारी - चीन और भारत 2020 में सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में उभर रहे हैं।

जनवरी के अंतिम सप्ताह में कुछ सुधार के साथ वित्तीय बाजारों ने आगे बढ़त हासिल की। सुधार कारकों के मिलने के कारण था, अर्थात्, अधिक संक्रामक वेरिएंट के तेजी से फैलने के बीच पैच वैक्सीन की तैनाती पर बढ़ती चिंताएं; यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए कमजोर आर्थिक डेटा; और अमेरिकी शेयर बाजारों में खुदरा निवेशकों द्वारा किए गए कार्यों ने कुछ हेज

फंडों को अभिभूत कर दिया। कुल मिलाकर, आई के लिए मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) स्टॉक इंडेक्स ने

महीने को लाल रंग में समाप्त कर दिया, जबकि उभरते बाजारों के लिए, एमएससीआई स्टॉक इंडेक्स ने शुद्ध लाभ (चार्ट 7) के साथ

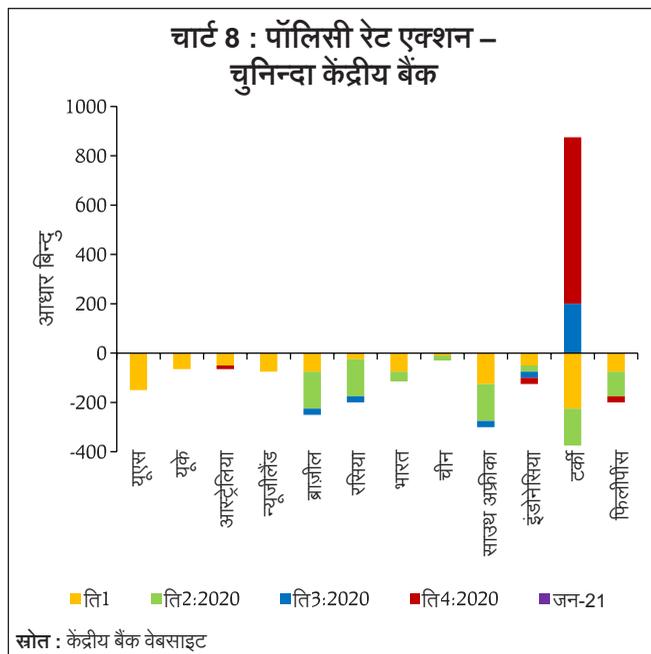
चार्ट 7 : वित्तीय बाजार



स्रोत : ब्लूमबर्ग और थॉमसन रायटर्स

महीने को समाप्त कर दिया। सेफ हैवेन परिसंपत्तियों की मांग में कमी के साथ, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बांड यील्ड कठिन हो गई, मार्च 2021 में पहली बार मार्च 2020 के बाद से 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड 1.0 प्रतिशत से अधिक हो गई। दूसरी ओर, उभरते बाजार में बॉन्ड यील्ड ने अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मिश्रित गति का प्रदर्शन किया, जो देश-विशिष्ट कारकों को दर्शाता है। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर जो 2020 में काफी कमजोर हो गया था, जनवरी में प्रमुख ई मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ, जो कि 0.7 प्रतिशत की बढ़त के साथ था। इसके अलावा, जनवरी में एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स (एमएससीआई-एम) इंडेक्स में 0.1 फीसदी की गिरावट आई, हालांकि कैपिटल इनफ्लो के चलते भारतीय रुपया और चीनी युआन मजबूत हुआ।

मौद्रिक नीति के मोर्चे पर, जनवरी 2021 (चार्ट 8) में ब्याज दरों पर यथास्थिति रखने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अत्यधिक व्यवस्थित बने हुए हैं। तुर्की, एकमात्र अपवाद, जिसने जनवरी 2021 में एक ठहराव बनाए रखने से पहले संचयी 875 आधार अंकों की दर से सितंबर 2020 के बाद से तीन चरणों में दरों को बढ़ाया है। ब्राजील के केंद्रीय बैंक ने अपनी जनवरी की बैठक में एक ठहराव बनाए रखा, लेकिन आगे दिए गए मार्गदर्शन को वापस ले लिया



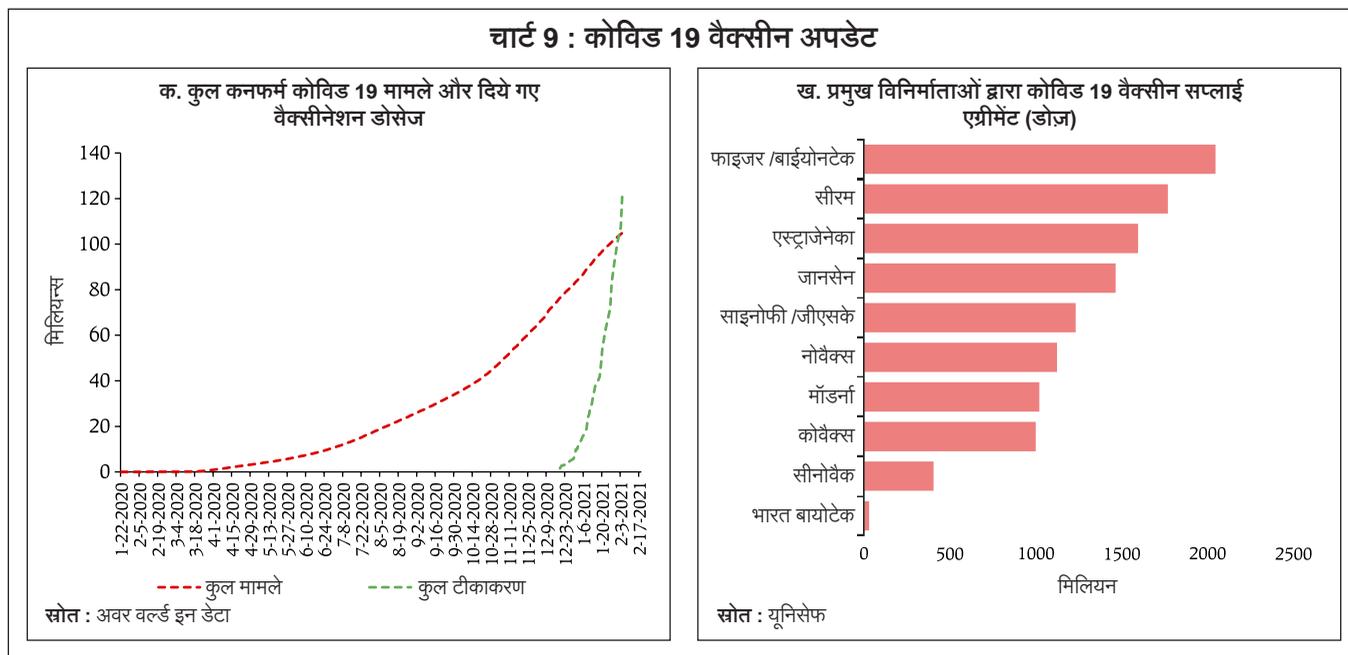
जो इसने अगस्त 2020 में मुद्रास्फीति की उम्मीदें और अनुमान लक्ष्य के करीब पहुंचने पर दिया था। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह कहा कि आगे के मार्गदर्शन को हटाने से ब्याज दर में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि विकास के संबंध में मौजूदा अनिश्चितताओं को असाधारण रूप से मजबूत मौद्रिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। राजकोषीय मोर्चे पर, दिसंबर 2020 तक वैश्विक स्तर पर कुल वित्तीय सहायता 14 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (आईएमएफ, फिस्कल मॉनीटर अपडेट) या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 13.5 प्रतिशत थी, जिसमें से 7.4 प्रतिशत राजस्व अग्रिम सीमा के रूप में था। अतिरिक्त खर्च और चलनिधि समर्थन के रूप में 6.1 प्रतिशत, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ऋण, गारंटी और इक्विटी इंजेक्शन शामिल हैं।

III. घरेलू विकास

भारत में, कोविड -19 की घटनाओं में कमी आने के कारण आर्थिक गतिविधियाँ समाप्त हो रही हैं और चल रहे वैकसीन रोलआउट ने छुपा हुआ आशावाद दर्शाया है। संकेतकों से प्राप्त जानकारी सामान्यीकरण की तेज गति से जुड़ी है। 31 जनवरी, 2021 तक भारत की साप्ताहिक कोविड -19 की मृत्यु दर 1000 से नीचे चली गई, जो पिछले 8 महीनों में सबसे कम थी। दोहरीकरण दर⁴ घटकर 578.3 दिन हो गई, सक्रिय मामलों में कुल मामलों का सिर्फ 1.4 प्रतिशत हिस्सा था। वास्तव में, 31 जनवरी, 2021 को सक्रिय मामलों की संख्या 1.7 लाख से नीचे चली गई थी। ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,05,34,505 हो गई है, जिससे ठीक होने की दर 97.0 प्रतिशत से अधिक हो गई है। फरवरी के मध्य से, हालांकि, कोविड -19 मामलों में उछाल आया है, जिसके परिणामस्वरूप दोहरीकरण दर 600 दिनों से कम हो गई है और सक्रिय मामले 27 फरवरी, 2021 तक 1.6 लाख अंक से अधिक है। भारत में उन लोगों में फिर से संक्रमण हो सकता है, जो पहले से ही एंटी-बॉडी विकसित कर चुके हैं।

जैसे कि दुनिया भर में टीकाकरण की गति तेज हो रही है, कोविड -19 टीकाकरण की कुल संख्या ने भारत सहित विश्व स्तर पर (चार्ट 9 ए) कोविड 19 के कान्फर्मर्ड मामलों की संख्या

⁴ दोहरीकरण दर को $\ln 2 / \ln(1+r)$ के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां r संचयी मामलों में वृद्धि के पिछले सात दिनों का औसत है।



को पार कर लिया है। वैक्सीन निर्माण में भारत वैश्विक अग्रणी होने के साथ, कई घरेलू वैक्सीन निर्माताओं ने मौजूदा बुनियादी ढांचे, विदेशी सहयोग और एक कुशल श्रम शक्ति (चार्ट 9 बी) का लाभ उठाकर कई देशों / एजेंसियों के साथ आपूर्ति समझौते किए हैं। "वैक्सीन मैत्री" पहल के तहत, अन्य विकासशील देशों के लिए पहल का विस्तार करने की योजना के साथ, पड़ोसी देशों को निःशुल्क वैक्सीन की आपूर्ति की गई है। कई अन्य देशों ने भारतीय फार्मा फर्मों से टीके आयात करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है, जिससे लागत प्रभावी तरीके से बड़ी संख्या में खुराक के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ हुआ है।

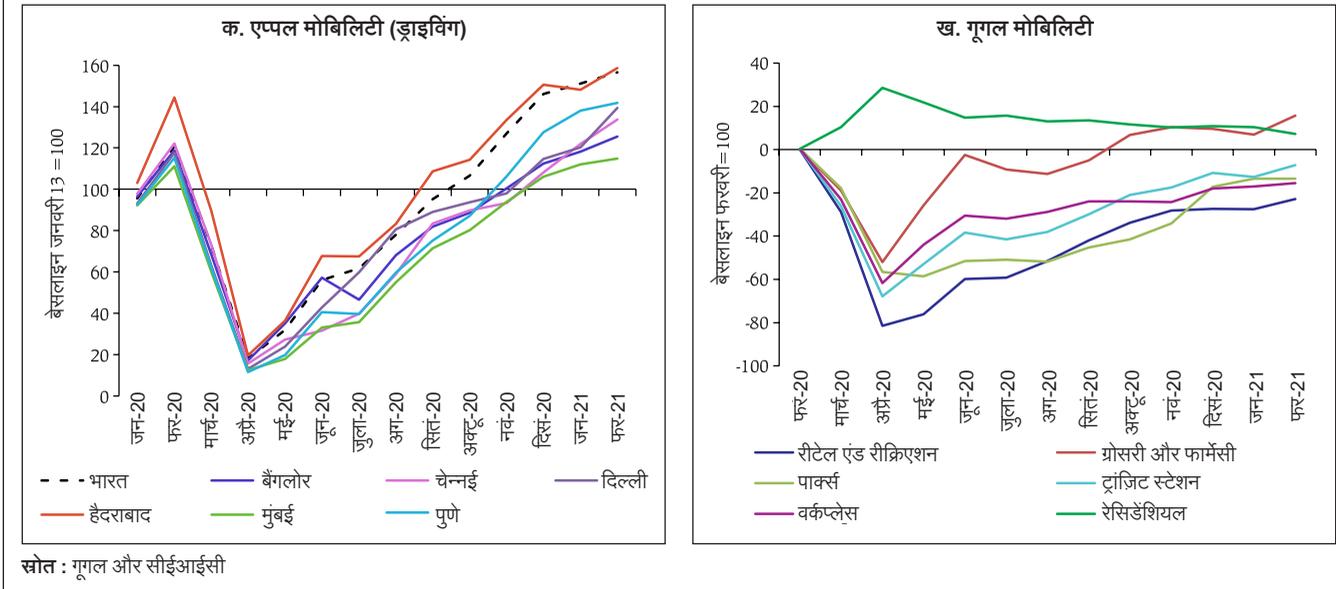
गतिशीलता संकेतक बताते हैं कि जनवरी और फरवरी 2021 में सभी प्रमुख शहरों में लोगों की आवाजाही पूर्व-महामारी के स्तर (चार्ट 10) की तुलना की जा सकती है। जबकि किराने के सामान और फार्मेशियों के आसपास की गतिशीलता जनवरी 2020 के स्तर से ऊपर हो गई है, देश के कुछ हिस्सों में प्रचलित छुट्टियों और कठोर सर्दियों की स्थिति के कारण ट्रांजिट स्टेशनों के आसपास गतिशीलता में कमी आई है। फरवरी 2021 में कार्यालयों में महामारी पूर्व के फुटफॉल्स का स्तर 84 प्रतिशत

तक पहुंच गया, जो पिछले महीने (मिट-ट्रैकर) में 82 प्रतिशत था। इसके साथ-साथ माल की आवाजाही काफी बढ़ गई, ई-वे बिल जनवरी में 10.5 प्रतिशत और फरवरी में 12.5 प्रतिशत बढ़ गया - अंतर-राज्य 13.0 प्रतिशत और 15.1 प्रतिशत: अंतर-राज्य 6.8 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत क्रमशः। उत्पाद और कारक गतिशीलता पूर्व-महामारी के स्तर पर तेजी से पहुंच गई और अर्थव्यवस्था में मांग में सुधार की गुंजाइश है।

कुल मांग

कुल मांग की स्थिति एक ऊंचे स्तर पर है। बिजली की चरम मांग 30 जनवरी को 189.6 गीगावाट तक पहुंच गई, जो 30 जनवरी को 189.6 गीगावाट तक पहुंच गया जिसने पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया। पांचवें और छठे क्रमिक महीनों के लिए जनवरी और फरवरी 2021 के माध्यम से बिजली की खपत का विस्तार जारी रहा, क्रमशः 4.8 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 11 ए)। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की निर्धारित नीतियों के परिदृश्य (एसटीईपीएस) के अनुसार, जो 2021 में धीरे-धीरे नियंत्रण में लाया जाएगा, भारत की कुल ऊर्जा मांग 2010 से 2040 तक (चार्ट 11 बी) 124.7 प्रतिशत तक बढ़ने वाली है।

चार्ट 10 : मोबिलिटी इंडिकेटर्स

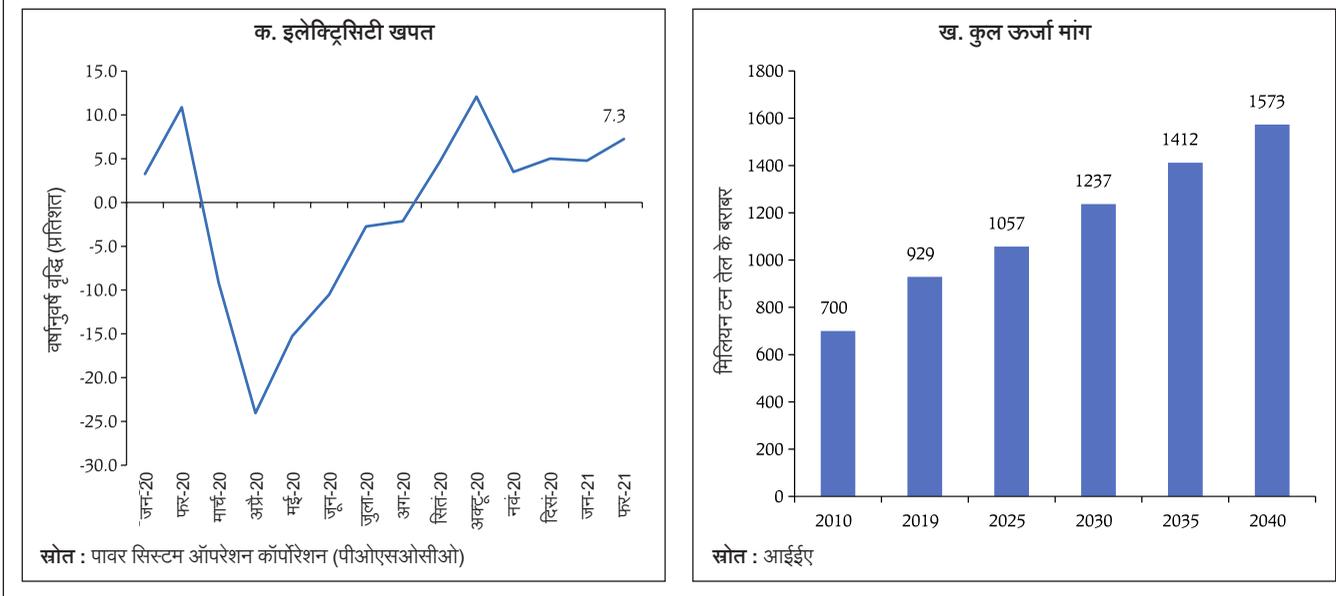


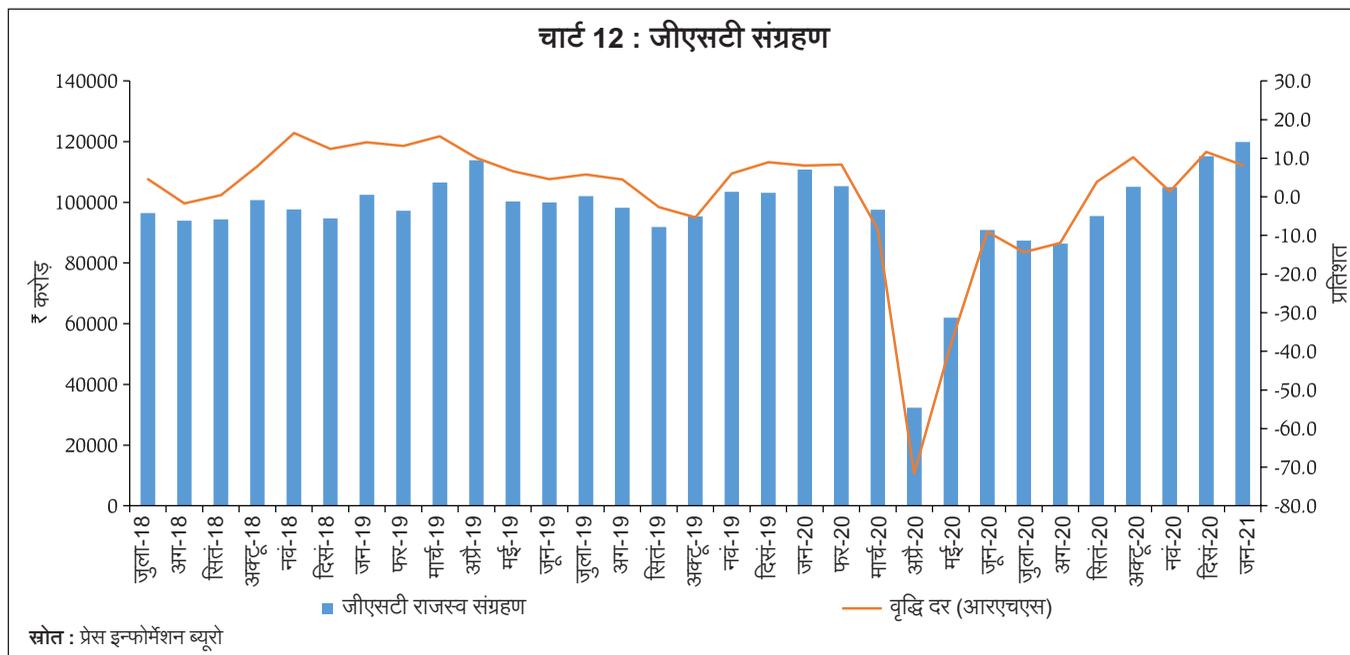
माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत संग्रहण जनवरी 2021 में चौथे महीने के लिए 1 लाख करोड़ की सीमा से ऊपर 1,19,847 करोड़ पर रहा। 8.1 फीसदी की वृद्धि के साथ, जीएसटी ने श्रृंखला (चार्ट 12) में उच्चतम मासिक संग्रह दर्ज किया। यह बेहतर कर अनुपालन के अलावा त्यौहारी सीज़न से आगे बढ़ते व्यापार और व्यापारिक कारोबार को प्रतिबिंबित करता है। असंतुष्ट अंतर-राज्य और अंतर-राज्य विश्लेषण से पता चलता

है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु हैं, जबकि गतिविधि मुख्य भूमि में कैच-अप मोड में रहती है जिसमें राजस्थान, दिल्ली, यूपी और हरियाणा (तालिका 2) शामिल हैं।

उपभोग की मांग की ओर रुख करते हुए, रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जनवरी 2021 के राउंड में टीकाकरण के आरंभ होने के कारण उत्पन्न सकारात्मक माहौल परिलक्षित

चार्ट 11: इलेक्ट्रिसिटी डिमांड





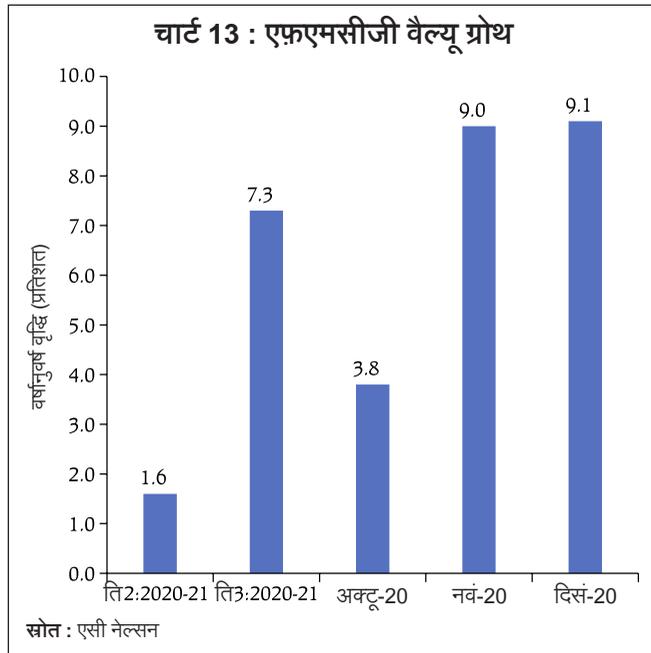
हुआ है। सितंबर 2020 से आयोजित सभी पूर्ववर्ती राउंड में धारणाओं में काफी सुधार हुआ है। आने वाले वर्ष के लिए, उपभोक्ताओं को सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार की स्थिति में समग्र सुधार की उम्मीद है। जबकि आवश्यक चीजों पर खर्च करने में सुविधा है, गैर-जरूरी खर्च के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। तेजी से बढ़ती उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी) कंपनियां बढ़ती गतिशीलता, आर्थिक गतिविधियों की बहाली, उपभोक्ता-प्रासंगिक नवाचारों और बाजार विकास में निवेश (चार्ट 13) की

मांग में वृद्धि की रिपोर्ट कर रही हैं। अधिकांश कंपनियों ने विवेकाधीन खर्चों में भी सुधार का अनुभव किया है जो गैर-टिकाऊ वस्तुओं की मांग में वृद्धि दर्शाता है। नील्सन इंडिया के अनुसार, स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में नए लॉन्च किए गए हैं, जिसमें प्रतिरक्षा एक 'न्यून नॉर्मल' के रूप में ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें हैंड सैनिटाइजर, फर्श क्लीनर, शौचालय क्लीनर और एंटीसेप्टिक लिक्विड जैसी श्रेणियां शामिल हैं। इन नए लॉन्च ने कोविड -19 अवधि में सभी नए लॉन्च के लिए मूल्य के संदर्भ में

सारणी 2 : ई वे बिल वृद्धि

	इंटर स्टेट (प्रतिशत में)										अंतर राज्य (प्रतिशत में)									
	अप्रै-20	मई-20	जून-20	जुला-20	अग-20	सित-20	अक्टू-20	नव-20	दिस-20		अप्रै-20	मई-20	जून-20	जुला-20	अग-20	सित-20	अक्टू-20	नव-20	दिस-20	
तेलंगाना	-87	-59	-5	0	-5	16	27	18	32	तेलंगाना	-53	-15	27	27	23	47	41	39	33	
पश्चिम बंगाल	-92	-74	-22	-20	-27	2	14	7	30	मध्य प्रदेश	-82	-34	19	30	33	47	37	20	27	
तमिलनाडु	-92	-66	-35	-23	-13	-2	32	10	23	पश्चिम बंगाल	-76	-52	6	8	6	18	35	18	27	
आंध्र प्रदेश	-83	-57	-9	-7	0	15	28	9	23	तमिलनाडु	-88	-54	-26	-16	-7	11	21	5	24	
गुजरात	-89	-66	-28	-16	-11	13	28	1	15	आंध्र प्रदेश	-65	-30	8	6	6	21	19	16	22	
महाराष्ट्र	-90	-68	-33	-24	-16	-4	11	7	14	कर्णाटक	-77	-35	1	-8	2	19	25	16	17	
कर्णाटक	-91	-62	-17	-18	-7	0	14	3	13	पंजाब	-82	-32	13	22	23	22	23	11	16	
पंजाब	-88	-52	-5	8	3	4	21	13	13	उत्तरप्रदेश	-78	-46	-3	2	-4	10	17	3	14	
मध्य प्रदेश	-91	-62	-15	-3	0	12	27	12	11	गुजरात	-81	-50	-12	-2	1	18	36	7	14	
राजस्थान	-93	-68	-19	0	4	6	19	6	10	दिल्ली	-82	-62	-25	-13	-11	0	8	0	14	
हरियाणा	-90	-63	-18	-5	-4	7	21	9	10	महाराष्ट्र	-85	-60	-23	-19	-7	7	17	6	12	
उत्तरप्रदेश	-91	-69	-10	-1	-4	0	18	10	8	हरियाणा	-91	-66	-20	-5	6	15	29	7	11	
दिल्ली	-90	-74	-37	-21	-21	-12	4	-2	6	राजस्थान	-81	-40	2	12	7	12	16	3	8	

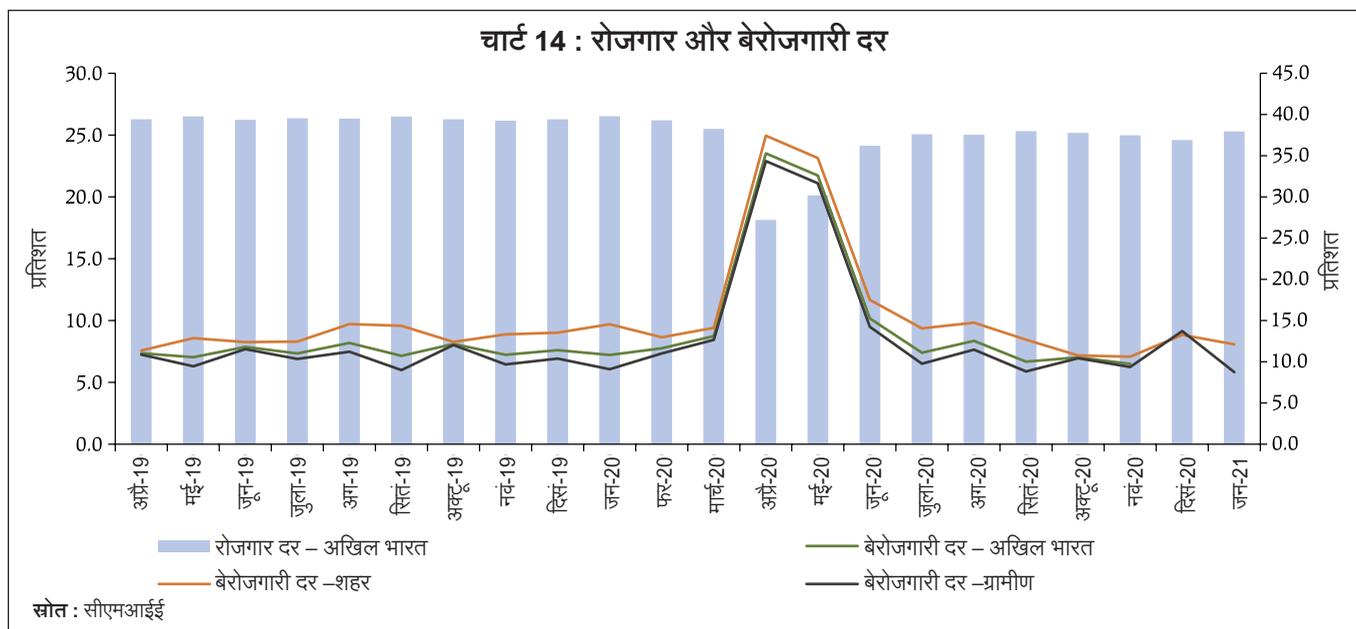
स्रोत : सीईसी



37 प्रतिशत का योगदान दिया। बड़ी एफएमसीजी कंपनियों के विज्ञापन / प्रचार खर्च पूर्व-महामारी स्तरों से अधिक थे। यात्री वाहनों के संबंध में, थोक बिक्री ने जनवरी 2021 में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले महीने में यह 13.6 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्र ने जून 2020 से ट्रैक्टरों की बिक्री में परिलक्षित होने वाली स्थिरता का प्रदर्शन किया है। लगातार 19 महीनों तक संकुचन में रहने के बाद, मोटरसाइकिल की बिक्री अगस्त 2020

में बढ़ गई और यह जनवरी 2021 में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए स्थिर बनी हुई है। 2021 जनवरी में रेलवे द्वारा किए गए माल ढुलाई में 8.7 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जबकि माल ढुलाई से होने वाली कमाई में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो माँग में प्रतिक्षेप के निरंतर स्थानिक विस्तार को रेखांकित करती है। ऑनलाइन खरीदारी की ओर उपभोक्ताओं के बीच एक बोधगम्य बदलाव भी आया है। एक यूनीकामर्स -कीरनी की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 की आखिरी तिमाही (अक्टूबर - दिसंबर) में क्रमशः ऑर्डर वॉल्यूम और ग्रॉस मर्चेडाइज वैल्यू (जीएमडबल्यू) के मामले में 36 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। सबसे बड़े लाभार्थी व्यक्तिगत देखभाल, सौंदर्य और कल्याण उत्पाद थे।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण में पाया गया है कि रोजगार की स्थिति जनवरी 2021 तक सुधरी है, जिसमें औसत रोजगार दर एक महीने पहले 36.9 प्रतिशत से बढ़कर 37.9 प्रतिशत थी। रियल एस्टेट, निर्माण और सेवाओं जैसे क्षेत्रों, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान रोजगार के नुकसान का सामना करना पड़ा है, जाहिर तौर पर पूर्व-कोविड स्तरों पर वापस आ गए हैं। नतीजतन, जनवरी 2021 में औसत बेरोजगारी दर घटकर दिसंबर 2020 (चार्ट 14) में 9.1 प्रतिशत हो गई। सुधार की गति शहरी क्षेत्रों की



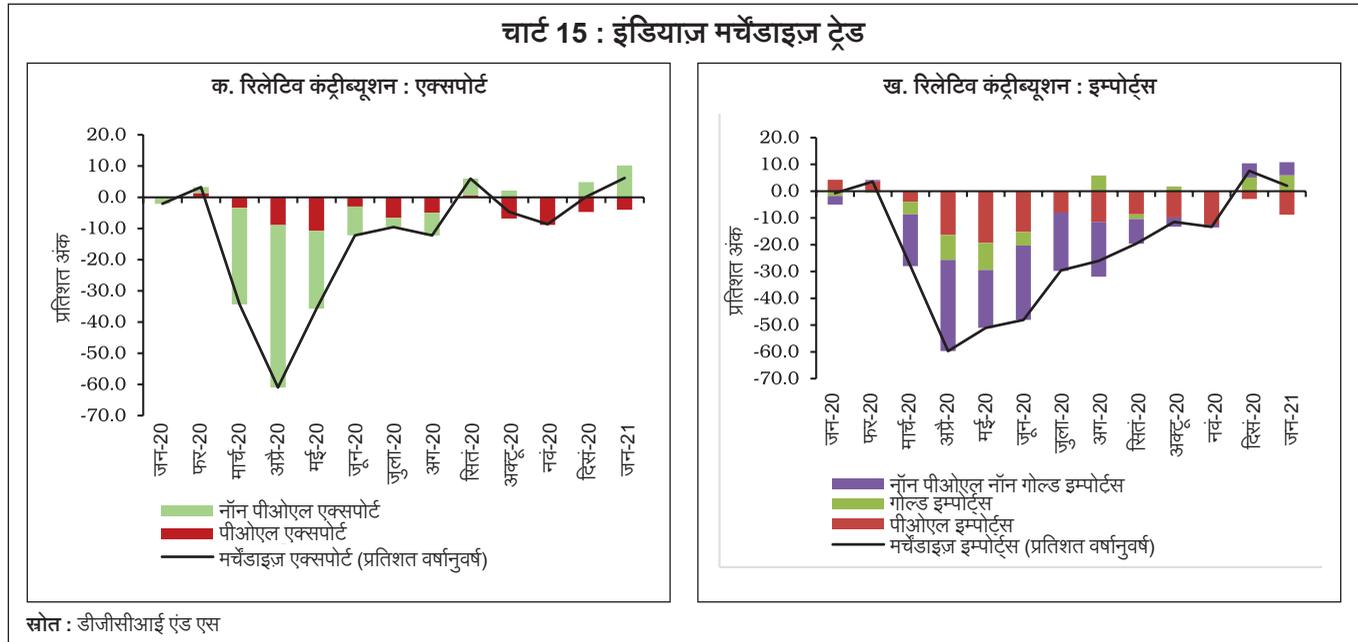
तुलना में ग्रामीण रोजगार के मामले में अधिक मजबूत थी, जो बताता है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जल्द ही कोविड-19 की दुर्बलतापूर्ण प्रतिबंधों को दूर कर रही है। वास्तव में, 5.8 प्रतिशत पर ग्रामीण बेरोजगारी दर जुलाई 2018 के बाद से सबसे कम है। हालांकि पिछड़ा हुआ शहरी रोजगार अब ठीक हो रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत रोजगार महामारी के दौरान लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ। तथापि, हाल ही में मनरेगा के तहत नौकरियों की मांग में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो वर्षानुवर्ष दिसंबर में 56.5 प्रतिशत से घटकर जनवरी में 37.3 प्रतिशत और फरवरी में 18.8 प्रतिशत हो गई (अब तक) जो अन्य गतिविधियों में बेहतर रोजगार के संकेत हैं। एक्सफ़ीनों के एक्टिव जॉब आउटलुक सर्वे के अनुसार जनवरी में कुल नौकरियों के अवसर पर एक महीने पहले से लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एंटी लेवल जॉब्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने इन जॉब ओपनिंग में सबसे ज्यादा योगदान दिया है।

बाहरी एनेमिक वातावरण को चुनौती देते हुए, भारतीय व्यापारिक निर्यातों में सतत वृद्धि परिलक्षित हुई, जो जनवरी 2021 में 6.2 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष) से बढ़ रहा था - विस्तार का लगातार दूसरा महीना। निर्यात में पिक-अप व्यापक आधारित रहा है, जो दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और लौह

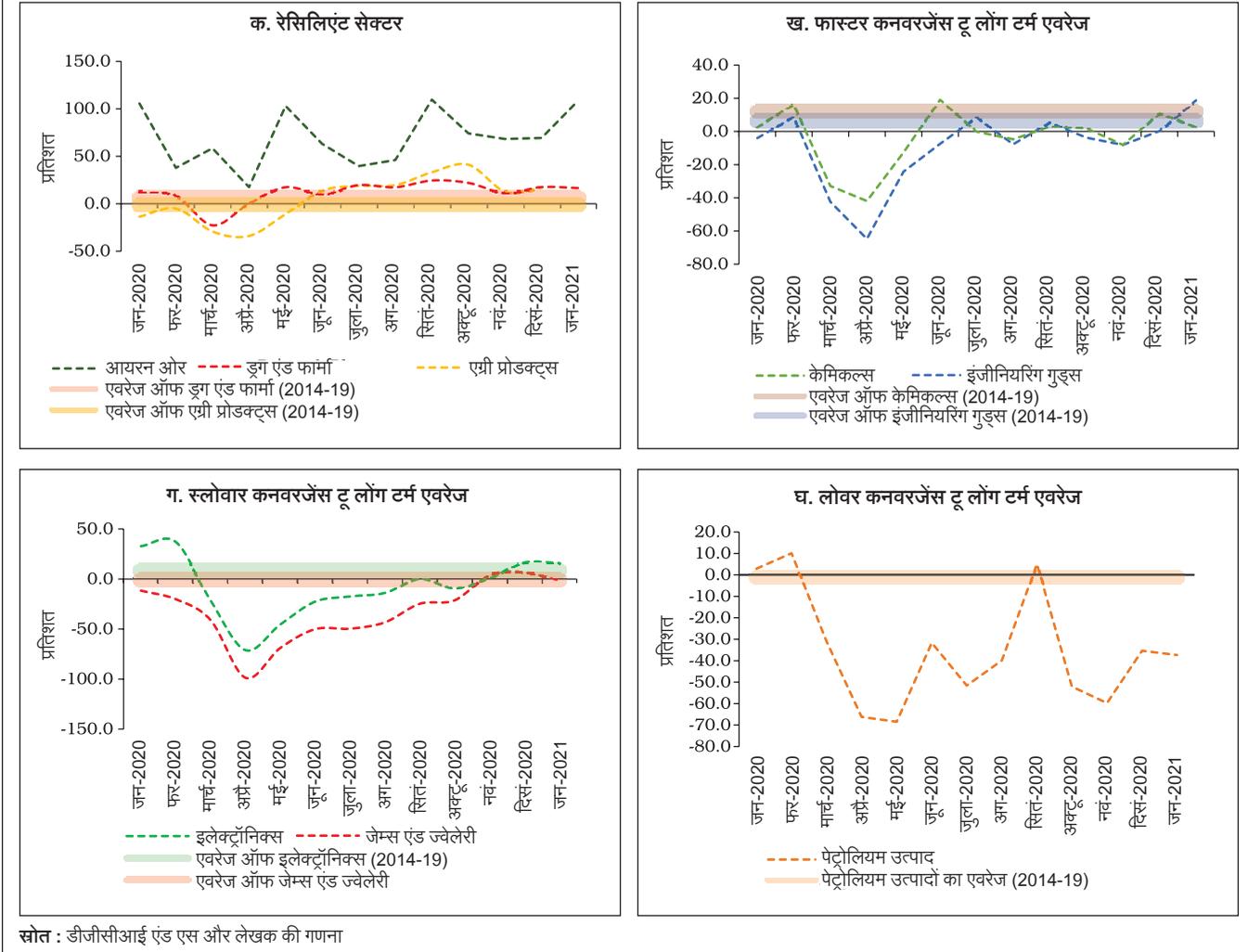
अयस्क के निर्यात के मजबूत प्रदर्शन द्वारा समर्थित है। एक अच्छा विकास यह है कि गैर-तेल निर्यात में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो लगातार पांचवें महीने के विस्तार (चार्ट 15 ए) को चिह्नित करता है। कुल मिलाकर, 30 प्रमुख वस्तुओं में से 22 या कुल निर्यात के 71.3 प्रतिशत समग्र निर्यात वृद्धि (चार्ट 16) में प्रमुख था। हाल के महीनों में, भारत एशियाई साथियों में एक व्यापक स्वैथ में शामिल हो गया है, जिसने इस क्षेत्र को महामारी के बाद निर्यात बहाली के मामले में दूसरों से ऊपर उठा दिया है।

जनवरी 2021 में भारत के माल आयात में लगातार दूसरे महीने 2.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो स्थायी (चार्ट 15 बी) हो रही घरेलू अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित विकास आवेगों की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। लंबे समय तक संकुचन से बाहर आयात में छूट भी 30 प्रमुख वस्तुओं में से 18 के साथ व्यापक आधारित रही है या कुल आयात का 60.7 प्रतिशत विस्तार दर्ज किया है। हालांकि वर्षानुवर्ष तेल आयात में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण गिरावट रही, गैर-तेल गैर-सोने के आयात में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोती और कीमती पत्थर शीर्ष तीन उच्च विकास आयात किए जाने योग्य वस्तुएं थीं, अनिवार्य रूप से घरेलू अंतिम उत्पादन और निर्यात में मध्यवर्ती थे।

चार्ट 15 : इंडियाज मर्चेडाइज़ ट्रेड



चार्ट 16 : रिकवरी प्रोसेस एक्रोस सेक्टर – कनवरजेंस टू लॉग टर्म एवरेज



भारत के कृषि निर्यात में पिछले आठ महीनों में प्रभावशाली वृद्धि हुई है, यानी, कोविड -19 के बावजूद, मई 2020 से लगातार, अनाज निर्यातों में एक शानदार प्रदर्शन के साथ। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, विशेषकर गैर-बासमती किस्मों का। कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय देशों में घरों में चावल के स्टॉक के कारण अंतरराष्ट्रीय मांग मजबूत हुई है, वियतनाम और थाईलैंड सहित अन्य प्रमुख निर्यातक आपूर्ति की गड़बड़ी से प्रभावित हुए हैं। गेहूं के संबंध में, यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट (यूएसडीए) ने 14 जनवरी 2021 को 1 मिलियन टन के अपने पहले के अनुमान के अनुसार, 2020-21 (जुलाई-जून) के लिए भारतीय गेहूं निर्यात के पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए 1.8

मिलियन टन (मीट्रिक टन) कर दिया है। 2020-21 में 3-4 मीट्रिक टन तक के निर्यात की संभावना वाले उद्योग प्रतिनिधियों के साथ। अगर देखा जाए, तो यह पिछले छह वर्षों में गेहूं का सबसे अधिक निर्यात होगा।

खाद्य प्रसंस्करण एक उदीयमान निर्यात क्षेत्र है जिसमें कृषि के साथ मजबूत संबंध हैं और यह उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत आता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हमारे निर्यात प्रोफाइल को कम-मूल्य वाले कच्चे माल के निर्यात एकाग्रता से उच्च-मूल्य वाले संसाधित माल निर्यात विशेषज्ञता में बदल सकता है। जैसा कि खाद्य प्रसंस्करण एक पूंजी-गहन उद्योग है, इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करना गेम चेंजर हो सकता है।

एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार माहौल और संरक्षणवाद के बढ़ते ज्वार के अलावा, भारत का विदेशी व्यापार वर्तमान में विकट तार्किक चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोविड -19 प्रेरित व्यवधानों और कंटेनरों की जमाखोरी के बाद कंटेनर माल की कीमतों में निरंतर वृद्धि ने निर्यातकों (चार्ट 17 ए) पर उच्च लागत लगाई है। वर्तमान में, भारत शिपिंग बेड़े (चार्ट 17 बी) के स्वामित्व के मामले में विश्व स्तर पर 18 वें स्थान पर है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में वैश्विक शिपिंग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय शिपिंग कंपनियों को समर्थन देने की योजना प्रस्तावित की गई है। इस प्रस्ताव से विदेशी संचालित शिपिंग कंपनियों पर भारतीय व्यापारियों की निर्भरता कम होने और कंटेनर उपलब्धता में आसानी होने की उम्मीद है।

आगे बढ़ते हुए, केंद्रीय बजट 2021-22 में सीमा शुल्क ड्यूटी स्ट्रक्चर के यौक्तिकीकरण पर प्रस्ताव, व्यापार सुगमता उपायों में सुधार, और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने पर इसका ध्यान (ईओडीबी) बुनियादी ढाँचे के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के साथ मिलकर भारतीय विनिर्माण की संभावनाओं को अनलॉक करके निर्यात को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

केंद्रीय बजट ने व्यय के एक प्रमुख पुनर्मूल्यांकन के भीतर आत्म निर्भर भारत के विषय को आगे बढ़ाते हुए सुधार की रणनीति के लिए एक अलग निवेश-समर्थक फोकस प्रदान किया

सारणी 3: प्रमुख राजकोषीय संकेतक
(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

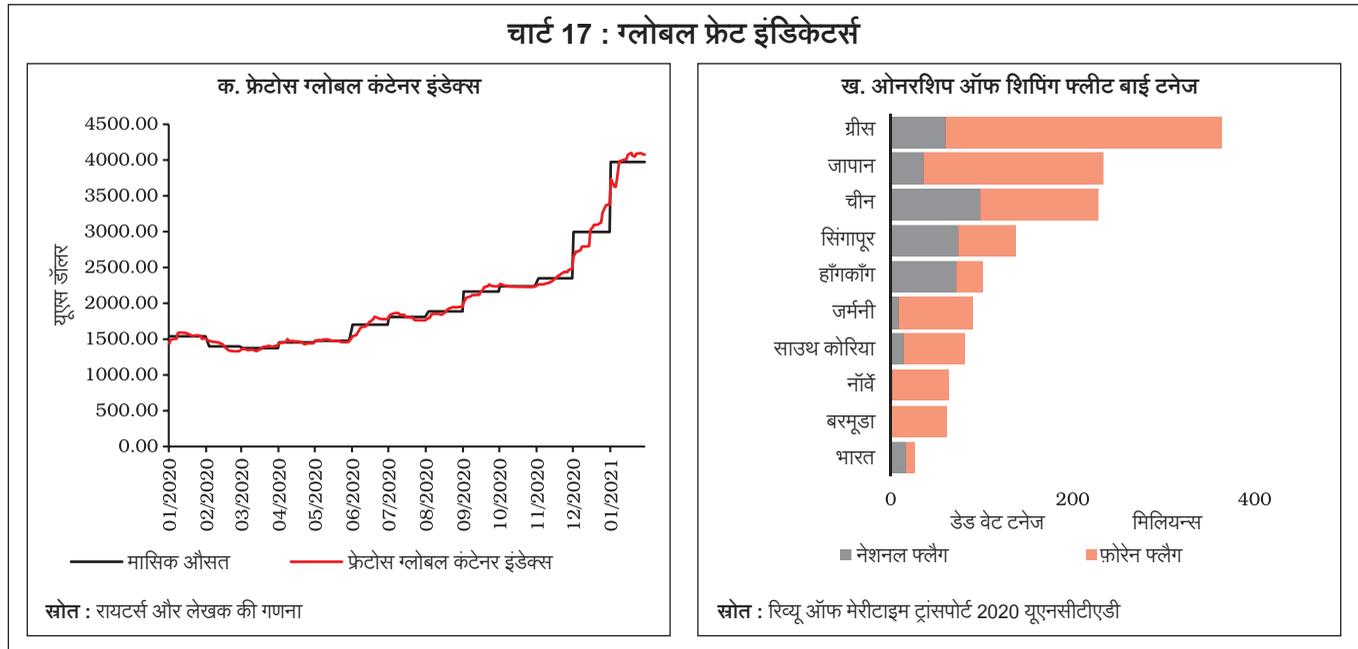
	2019-20	2020-21		2021-22
	वास्तविक	बीई	आरई	बीई
1. सकल राजकोषीय घाटा	4.6	3.5	9.5	6.8
2. राजस्व की कमी	3.3	2.7	7.5	5.1
3. प्राथमिक कमी	1.6	0.4	5.9	3.1
4. सकल कर राजस्व	9.9	10.8	9.8	9.9
5. गैर-कर राजस्व	1.6	1.7	1.1	1.1
6. राजस्व व्यय	11.6	11.7	15.5	13.1
7. पूंजीगत व्यय	1.6	1.8	2.3	2.5
8. केंद्र सरकार ऋण	52.3	50.6	64.3	62.5

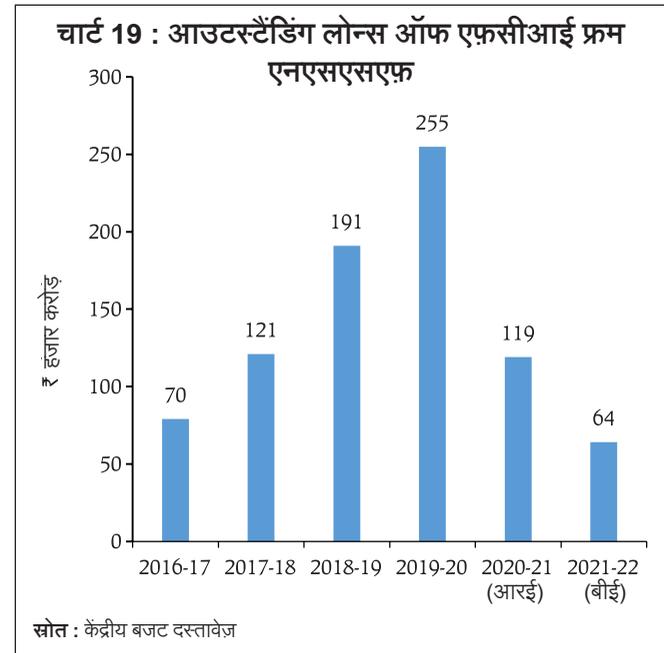
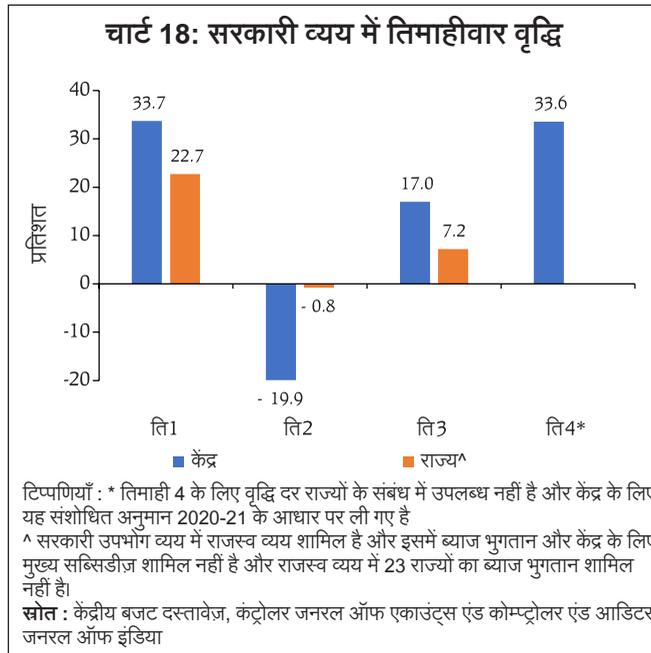
स्रोत: केंद्रीय बजट

है। 2010-20 के दौरान पूंजीगत व्यय जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के औसत से 2021-22 में 1.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, यहां तक कि राजस्व व्यय को भी 2020-21 में अपने स्तर से जीडीपी के अनुपात के रूप में अनुबंधित करने के लिए निर्धारित है (आरई) (तालिका 3)।

2020-21 में सामान्य सरकारी खपत व्यय में तिमाही गतिविधियों से पता चलता है कि ति.3 में राजस्व व्यय पर नए सिरे से जोर दिया गया है, जो कि ति.4 में और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि राज्यों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में उच्च व्यय प्राप्त होता है। केंद्र के लिए, ति.4 में लगभग 110 प्रतिशत

चार्ट 17 : ग्लोबल फ्रेट इंडिकेटर्स





की राजस्व व्यय वृद्धि की परिकल्पना की गई है। हालांकि, इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण अनुपात सब्सिडी के बजट पर / पिछले बकाया की मंजूरी के कारण है; इसलिए राजस्व व्यय कम ब्याज भुगतान और प्रमुख सब्सिडी, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का एक बेहतर संकेतक, ति. 4 (चार्ट 18) में 33.6 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

निवेश के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन बेहतर अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व की उछाल को बढ़ाकर (i) हासिल करना चाहता है; और (ii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) और सरकारी मंत्रालयों / विभागों के साथ अधिशेष भूमि सहित परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्तियां जुटाकर। इसके अलावा, विनिवेश से प्राप्तियां रु. 1.75 लाख करोड़ हैं, जिसमें दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण शामिल है।

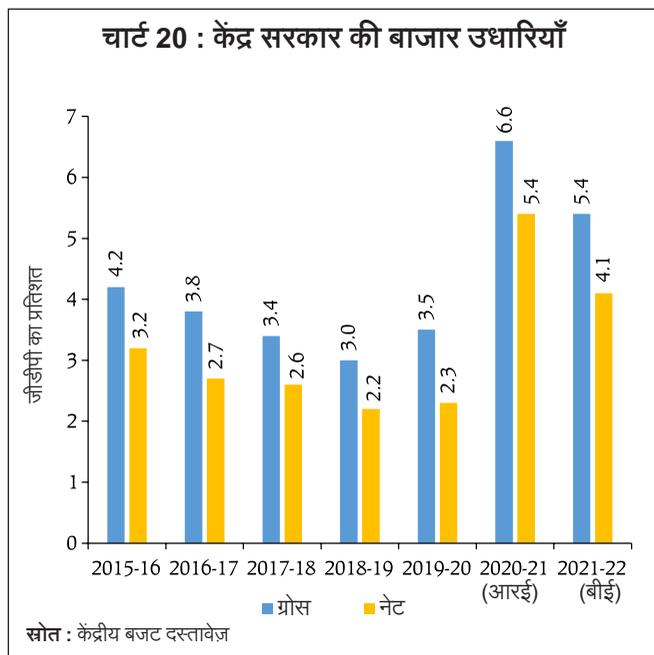
कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट मुद्रास्फीति विरोधी बने रहने की उम्मीद है। व्यय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नेशनल स्मॉल सेविंग फंड (एनएसएसएफ़) से भारतीय खाद्य निगम (एफ़सीआई) द्वारा सब्सिडी के एवज में प्राप्त बकाया ऋणों के ऑन-बजट के कारण है, जो 2016-17 के बाद से चली आ रही

प्रथा है (चार्ट 19)। वास्तव में, कुल व्यय में केवल 1 प्रतिशत का विस्तार होने का अनुमान है, राजस्व व्यय में 2.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। नए कृषि अवसंरचना विकास उपकरण (एआईडीसी) के मुद्रास्फीति प्रभाव को पेट्रोल और डीजल के मामले में आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क और संघ उत्पाद शुल्क में कटौती / युक्तिकरण द्वारा काफी हद तक ऑफसेट किया जाता है।

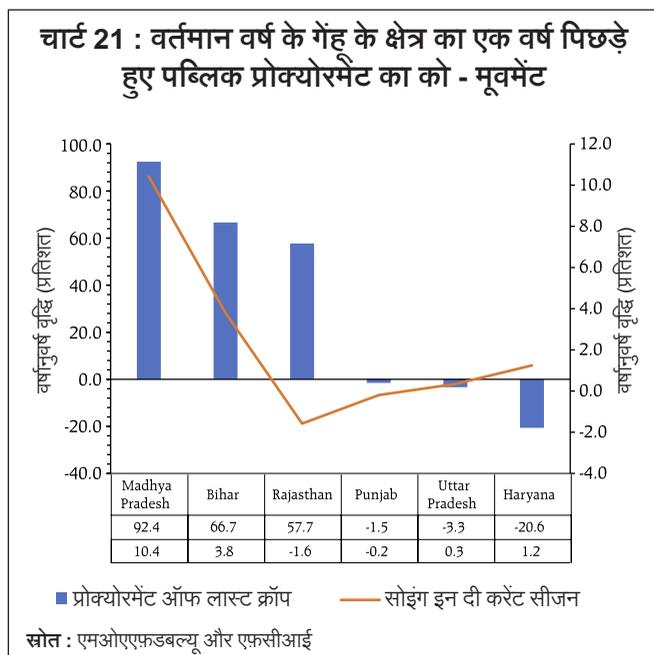
जब केंद्र के सकल और शुद्ध बाजार उधार दोनों को एक साल पहले की तुलना में जीडीपी के संदर्भ में कम किया जाता है (चार्ट 20)।

सकल आपूर्ति

जनवरी 2021 के माध्यम से सकल आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ। रबी की बुआई का मौसम पूरा होने के साथ, फसल की बुआई 684.6 लाख हेक्टेयर में पूरी हो गई है - पिछले वर्ष की तुलना में 2.9 प्रतिशत अधिक और पूर्ण सीजन की सामान्य एकरेज (5-वर्ष की औसत) की तुलना में 10.4 प्रतिशत अधिक (तालिका 4)। यह आजादी के बाद सबसे अधिक बोया गया क्षेत्र है, जो एक और रिकॉर्ड उत्पादन के लिए अच्छी तरह से तैयार है।



गेहूँ के नीचे की कवरेज प्रभावशाली रही है, जो सामान्य बुवाई से 14.1 प्रतिशत अधिक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), पर्याप्त सिंचाई और अनुकूल मिट्टी की नमी की स्थिति जारी रखने की प्रतिबद्धता कृषि (चार्ट 21) के लिए अच्छी है। इंटररेगनम में, अनाज का स्टॉक बफर मानदंडों से 3.9 गुना अधिक हो गया है।



तालिका 4: अखिल भारतीय फसल स्थिति - रबी (2020-21) 29 जनवरी, 2021 को

(लाख हेक्टेयर में)

फसल का नाम	पूरे सीजन के लिए सामान्य क्षेत्र	तिथि के अनुसार बुवाई करें		सामान्य पूर्ण मौसम पर प्रतिशत भिन्नता
		इस वर्ष (2021)	पिछले साल (2020)	
1. गेहूँ	303.3	346.4	336.4	14.2
2. चावल	41.8	35.2	30.2	-15.7
3. मोटे अनाज	57.1	51.7	56.1	-9.6
ए. ज्वार	33.4	27.2	30.2	-18.6
बी. जौ	6.4	6.8	7.8	7.3
सी. मक्का	17.4	16.9	17.5	-2.5
4. कुल दालें	144.9	167.4	162.9	15.5
ए. ग्राम	92.8	112.0	107.3	20.7
बी. मसूर	14.2	16.5	16.1	16.2
सी. मटर	8.8	10.7	11.0	21.7
डी. कुल्थी (हॉर्स ग्राम)	2.2	3.9	5.2	79.7
इ. उड़द	8.9	8.1	7.5	-9.4
एफ. मूंग	9.9	6.6	6.7	-33.1
जी. लेथिरस	4.0	3.1	3.3	-21.8
1. कुल खाद्यान्न (1+2+3+4)	547.1	600.6	585.6	9.8
5. तिलहन	73.2	84.0	80.0	14.7
ए. रेपसीड एंड मस्टर्ड	59.4	73.9	69.1	24.4
बी. मूंगफली	7.3	4.8	4.8	-34.6
सी. सूरजमुखी	2.4	1.0	1.0	-56.9
डी. तिल	0.0	0.5	0.6	0.0
इ. कुसुम	1.2	0.6	0.6	-50.6
एफ. अलसी का बीज	2.7	2.9	3.5	6.9
सभी फसलें (1+2+3+4+5)	620.3	684.6	665.6	10.4

नोट: क्षेत्र के आंकड़े राज्य के कृषि विभागों के आंखों देखे आकलन के अनुसार हैं। सामान्य क्षेत्र: 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान औसत क्षेत्र। स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएफ़डबल्यू)

तिलहनों के बीच, सरसों और रेपसीड ने इस साल बोए जाने वाले क्षेत्र के समंध में एक रिकॉर्ड दर्ज किया - सामान्य क्षेत्र की तुलना में 14.7 प्रतिशत अधिका दालों के क्षेत्र में वृद्धि भी इस साल बेहतर उत्पादन का संकेत देती है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रीय बजट का ध्यान, संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के साथ-साथ मत्स्य पालन और समुद्री शैवाल की खेती को प्रोत्साहन रोजगार बढ़ाकर और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करके कृषि विकास को और अधिक बढ़ा सकता है। बजट में 'ऑपरेशन ग्रीन' को वर्तमान में कवर करने वाली 3 फसलों (प्याज,

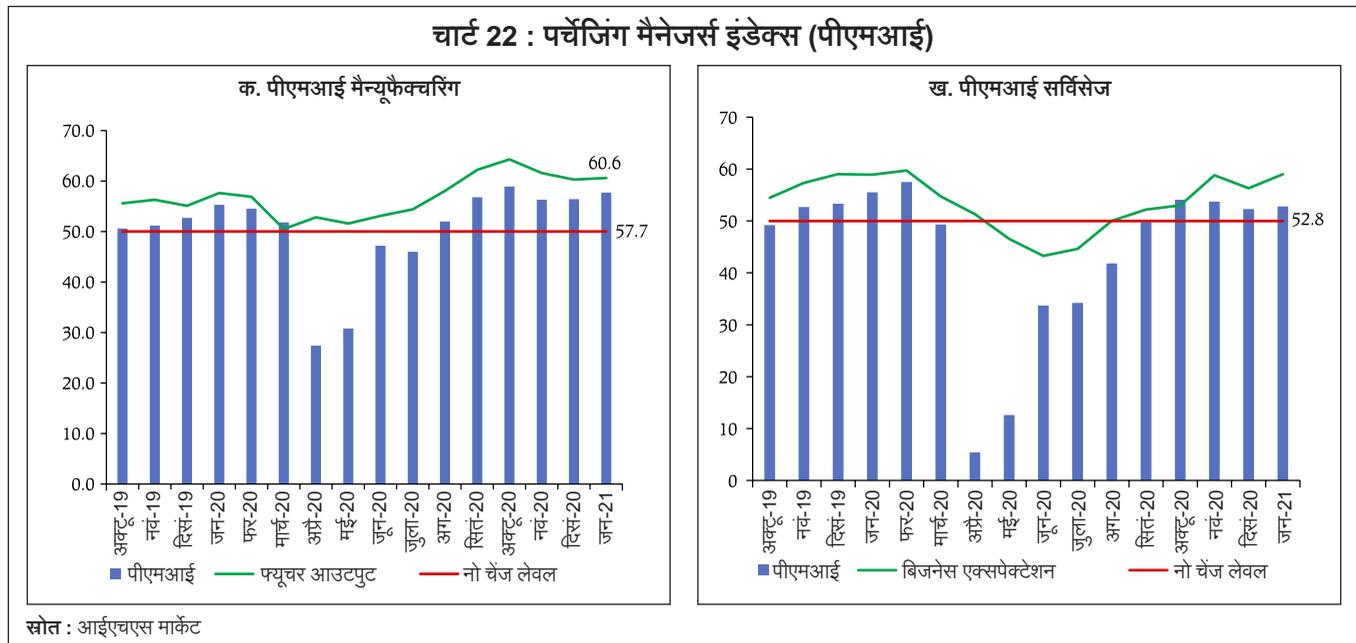
टमाटर और आलू) से 22 खराब होने वाली वस्तुओं के विस्तार का प्रस्ताव है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, अत्यधिक मूल्य को कम करने और खराब कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के लिए कृषि अवसंरचना कोष का विस्तार और पहले से ही विकसित 1,000 मंडियों के शीर्ष पर ई-एनएएम⁵ के साथ अतिरिक्त 1,000 एपीएमसी मंडियों के एकीकरण से विपणन दक्षता को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे आने वाले वर्षों में बेहतर पहुंच और पारिश्रमिक रिटर्न वाले किसानों को लाभ होगा। बीमा में एफडीआई की सीमा में वृद्धि से किसानों और ग्रामीण बाजारों के लिए अधिक अनुकूल बीमा विकल्प लाने में सक्षम होने के लिए स्टार्ट-अप के लिए बाजार का विस्तार करने में मदद मिलनी चाहिए।

उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र (चार्ट 22) में बिक्री में तेजी के कारण नए ऑर्डर और आउटपुट में एक महीने पहले जनवरी 2021 में हेडलाइन विनिर्माण पीएमआई 56.7 से बढ़कर 57.7 हो गई। ति.3: 2020-21 में रिजर्व बैंक के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (आईओएस) के 92 वें दौर के उत्तरदाताओं ने सकारात्मकता को समाप्त कर दिया, जिसमें व्यापारिक उम्मीद सूचकांक लगातार दो तिमाहियों में उभर रहा था। विनिर्माणकर्ता

आगे के महीनों में उत्पादन, ऑर्डर बुक और रोजगार को मजबूत करते हैं, जो व्यवसायों के अनलॉक और पुनः प्रारंभ द्वारा संचालित होते हैं। बैंकों और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से वित्त की उपलब्धता पर उनकी भावनाओं में सुधार हुआ। अगली तीन तिमाहियों में, अर्थात् ति. 4: 2020-21 और 2021-22 की ति. 1 और ति. 2, फर्म मांग की स्थिति और रोजगार के संबंध में उत्साहित हैं।

सेवा क्षेत्र में, वसूली व्यापक-आधारित प्रतीत होती है। पीएमआई सेवाओं का विस्तार जनवरी 2021 में लगातार चौथे महीने (52.3 से एक महीने पहले) के लिए किया गया, जो नए काम और बढ़ी हुई व्यावसायिक गतिविधि द्वारा समर्थित है। मूल्य छूट, विपणन रणनीति, और कुछ दुकानों के फिर से खोलने के साथ-साथ समग्र मांग में बिक्री में वृद्धि हुई है। टीकाकरण अभियान के प्रकाश में, जनवरी 2021 में व्यावसायिक उम्मीदों में ग्यारह महीने के उच्च स्तर 59.0 पर सुधार हुआ। यह सुधार रिजर्व बैंक की सेवाओं और बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 27 वें दौर में भी दिखाया गया था जो ति.3: 2020-21 में आयोजित किया गया था। फर्मों को ति.4: 2020-21 में कारोबार में और उन्नति की उम्मीद है।

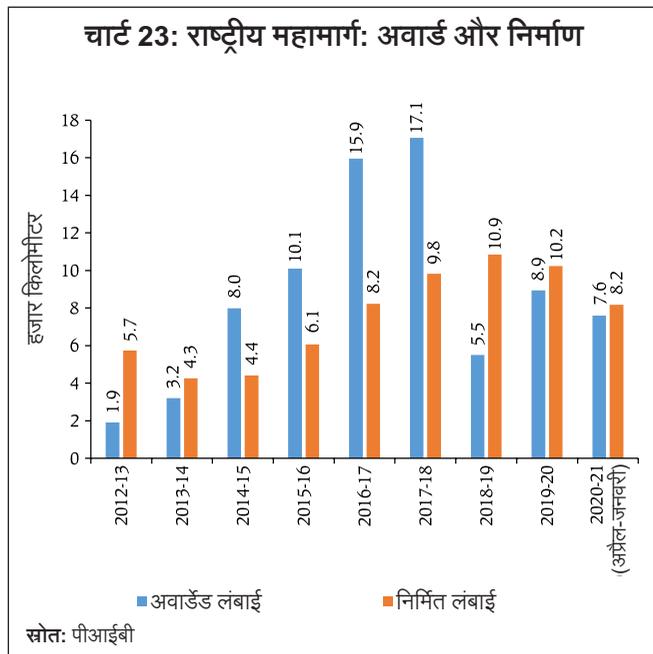
चार्ट 22 : पचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई)



⁵ राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईनाम) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा एपीएमसी मंडियों को कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए नेटवर्क प्रदान करता है।

बिक्री मूल्य में वृद्धि की संभावना इनपुट लागत में वृद्धि की भरपाई होगी, जिससे लाभ मार्जिन बढ़ेगा।

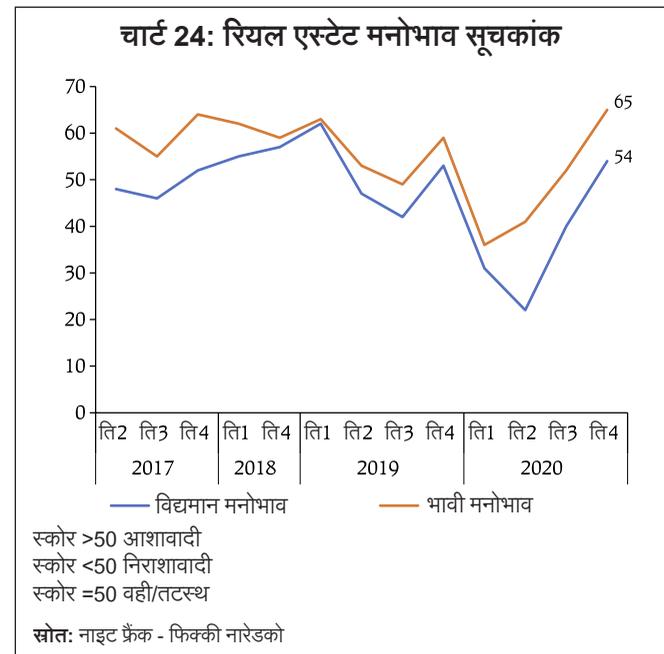
सेवाओं की विशिष्ट श्रेणियों में, निर्माण गतिविधि गति प्राप्त कर रही है, इस्पात की बढ़ती खपत से यह स्पष्ट है, जनवरी 2021 में इसमें 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। सड़क परिवहन और महामार्ग मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2020-21 (अप्रैल-15 जनवरी) के दौरान 28.16 किलोमीटर की दूरी का दैनिक सड़क निर्माण किया गया, जो पिछले साल के 26.11 किलोमीटर से अधिक है। इसी अवधि के दौरान निर्माण के लिए प्रदान की गयी 7,573 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई भी दोगुनी हो गई। 15 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान, 534 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गों की रिकॉर्ड लंबाई का निर्माण किया गया था। 31 मार्च तक 11,000 किलोमीटर निर्माण की गति का लक्ष्य बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते चालू वित्त वर्ष के शेष महीने निर्माण गतिविधि के लिए अनुकूल हैं। राष्ट्रीय महामार्गों की निर्माण के लिए प्रदान की गई और निर्मित लंबाई की तुलना से यह संकेत मिलता है कि निर्माण के लिए प्रदान की गयी तथा निर्मित दोनों लंबाई में निर्मित लंबाई ने शुरुआती महीनों ⁶ में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद वृद्धि दर्ज की (चार्ट 23)।



⁶ <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1689402>

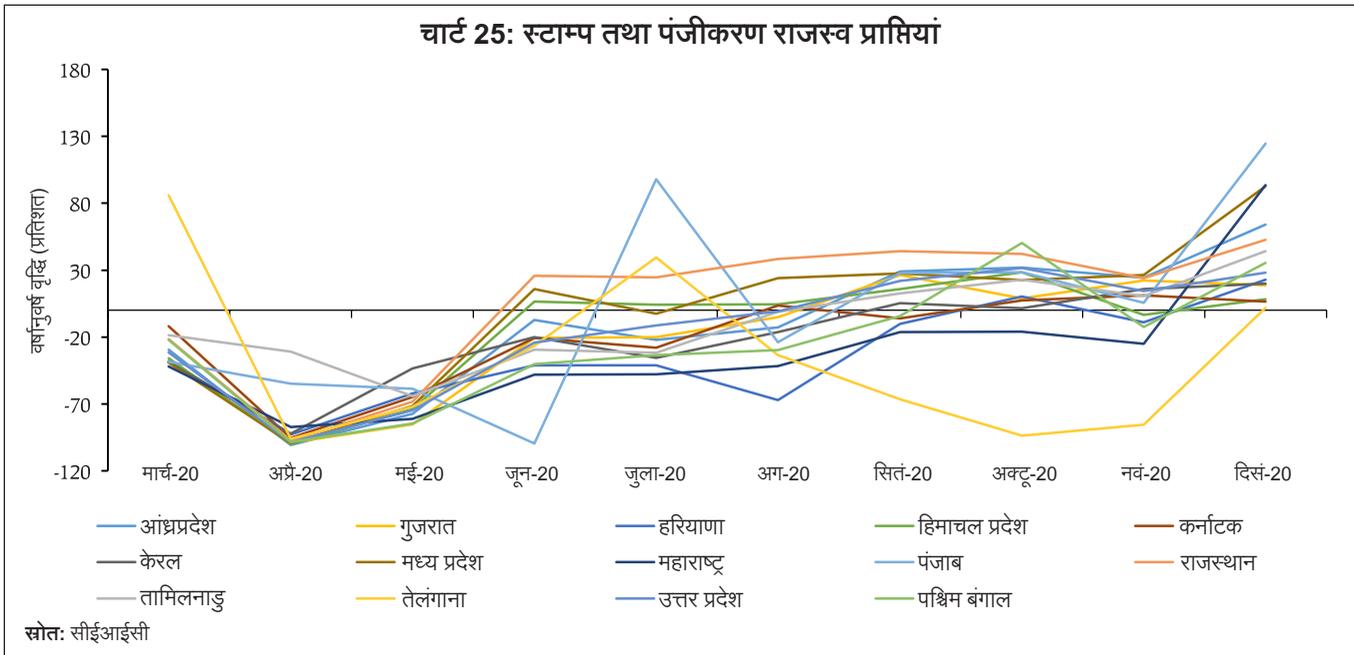
रियल एस्टेट क्षेत्र में, दिसंबर 2020⁷ को समाप्त तिमाही में नवीनतम रिलीज से संकेत मिलता है कि आवास में आठ तिमाहियों में पहली बार वृद्धि की शुरुआत हुई है, जिससे बाजार के मनोभाव तीन साल के उच्च स्तर ⁸ पर पहुंच गए हैं। रियल एस्टेट सेंटीमेंट्स इंडेक्स, जो 2020 की दूसरी तिमाही में अब तक के सबसे निचले स्तर तक गिर गया था, आवासीय इकाइयों और कार्यालय दोनों की मांग बढ़ने के कारण 2020 की चौथी तिमाही में आशा बढ़ी है। देश के पश्चिमी भाग में भावी मनोभाव सूचकांक में सबसे तेज उछाल निकट भविष्य में देश भर में और हितधारकों में आशावाद को दर्शाता है। 27 जनवरी को जारी नाइट फ्रैंक-फिक्की-नारेडको रियल एस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्स सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि रियल एस्टेट क्षेत्र अगले छह महीनों में तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है और उत्तर भारत की तुलना में "मनोभाव" पूर्व, दक्षिण और पश्चिम भारत में बहुत अधिक है। (चार्ट 24)।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्टांप शुल्क कम करने जैसे उपायों ने भी आवास की मांग को बढ़ावा देने में मदद की है। राज्यवार मासिक स्टांप और पंजीकरण राजस्व प्राप्ति में भी रियल एस्टेट क्षेत्र में एक स्थिर पिकअप की पुष्टि करता है (चार्ट 25)।



⁷ प्रॉपटीगर डेटा रिलीज

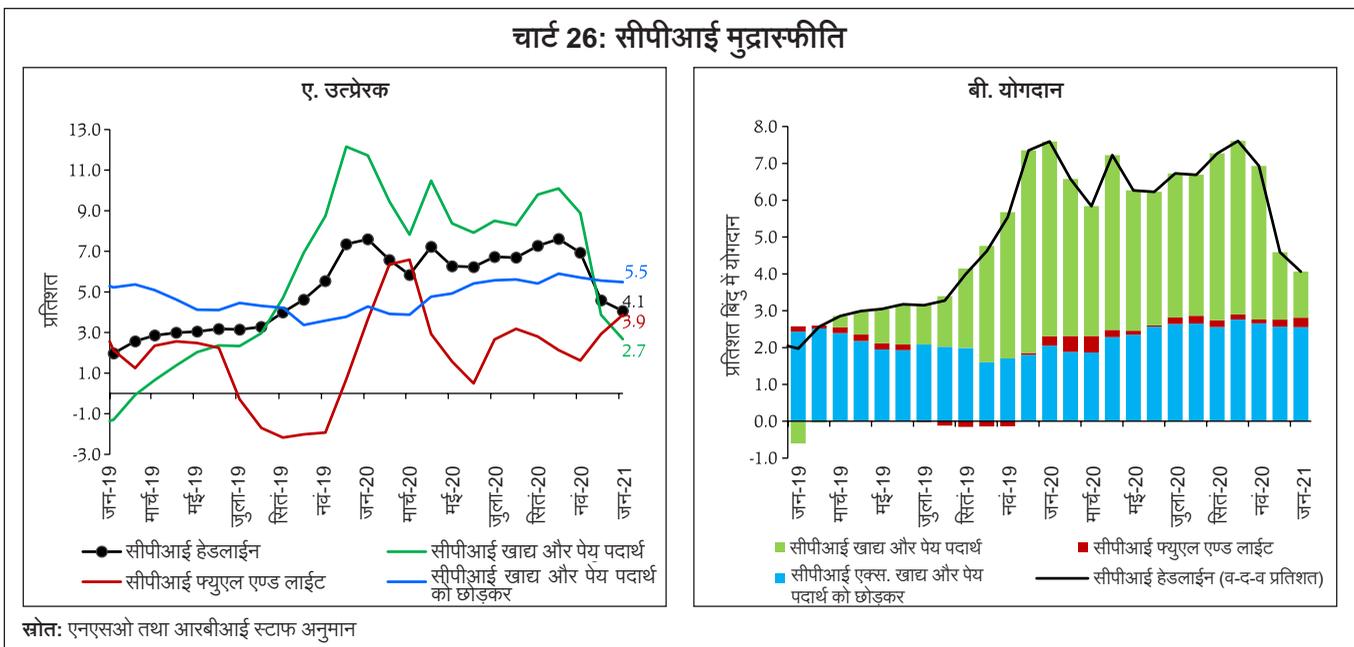
⁸ रियल एस्टेट मनोभाव सूचकांक- नाइट फ्रैंक, नारेडको और फिक्की



मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति में जनवरी 2021 में भी लगातार नरमी जारी रही, जो एक महीने पहले के 4.6 प्रतिशत से घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई। इसके पीछे खाद्य मुद्रास्फीति में दिसंबर के 3.9 प्रतिशत में-120 आधार अंक (बीपीएस) की तीव्र गिरावट है (चार्ट 26 ए)। सब्जियों और चीनी

की कीमतों में गिरावट, अनाज, अंडे, मांस, मछली, दूध, दाल और मसालों की कीमतों में गिरावट ने इस बहाली में पर्याप्त योगदान दिया। हालांकि, दिसंबर में ईंधन की महंगाई दर 2.9 प्रतिशत से घटकर 3.9 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से एलपीजी मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण हुई। 5.5 प्रतिशत पर खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई स्वास्थ्य, पेट्रोल, डीजल, मोटर वाहनों,



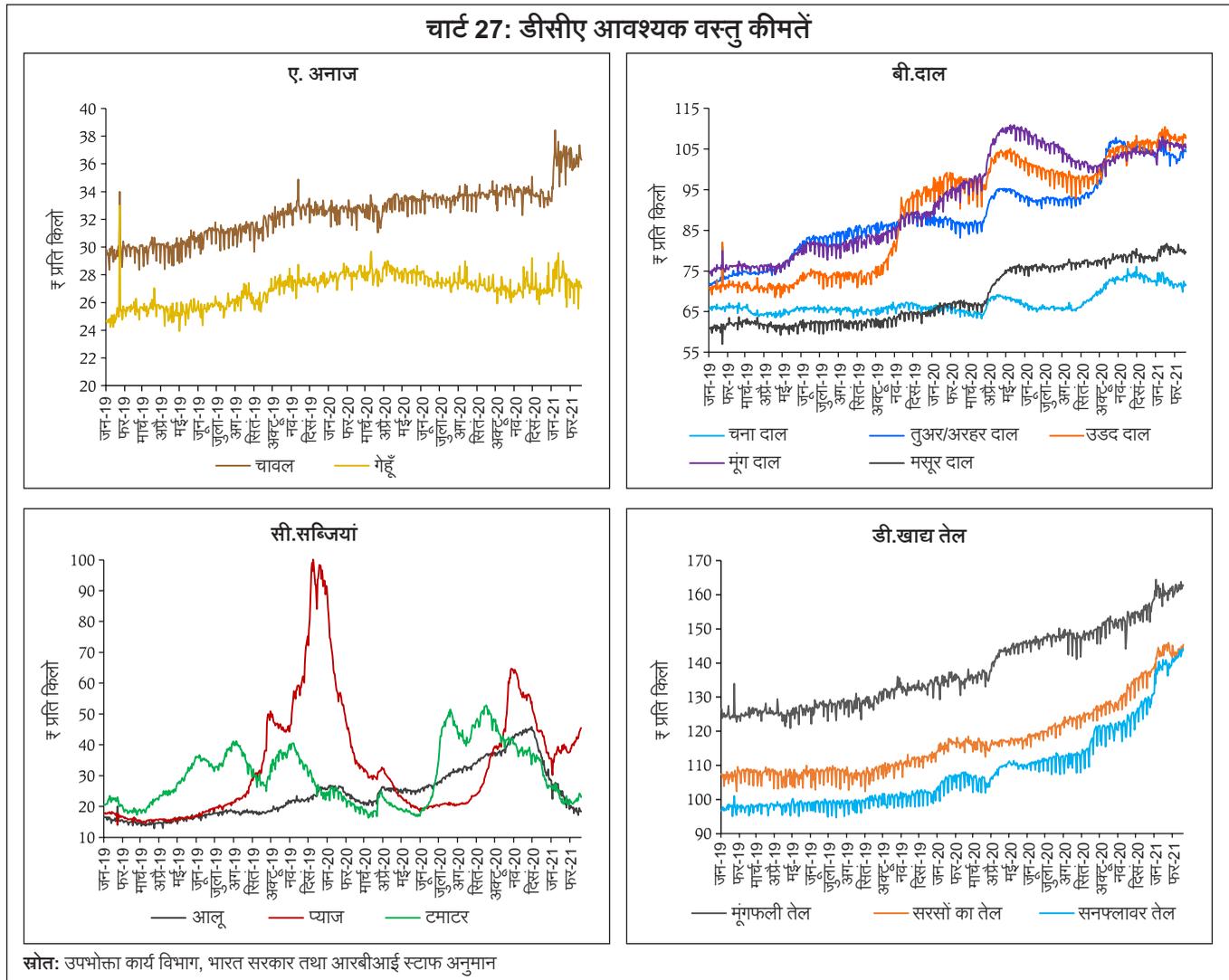
परिवहन किरायों और मनोरंजन सेवाओं में मूल्य दबाव जारी रहा। लॉकडाउन के पश्चात निजी देखभाल के सामान, सोना, पान, तंबाकू और नशिले पदार्थों की कीमतों के कारण दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति जारी रही। जहां कपड़ों में मुद्रास्फीति ज्यादा रही, वही आवास, घरेलू सामान तथा सेवाओं और शिक्षा में मुद्रा सफीति कम रही। खाद्य और ईंधन के अलावा सीपीआई ने (47.3 प्रतिशत भार के साथ) समग्र हेडलाइन मुद्रास्फीति में 63 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट 26 बी)।

उपभोक्ता मामलें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामलें विभाग) से उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य डेटा फरवरी के लिए अब तक (1-12 फरवरी) अनाज और सब्जियों के संबंध में मूल्य दबावों में महीने-दर-महीने नरम होने का संकेत देते

हैं। दालों की कीमतों में समान रूप से नरमी दर्ज की है, हालांकि अभी भी ऊंचे स्तर पर है। सब्जियों में, आलू और टमाटर की कीमतों में मौसमी गिरावट देखी गयी; यद्यपि, बेमौसम बारिश के कारण प्याज की कीमतों में तेजी आई है। फरवरी में खाद्य तेल की कीमतें और बढ़ गईं (चार्ट 27)।

भारतीय बास्केट कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं, जनवरी के 55 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से फरवरी में अब तक (1-12 फरवरी) 59 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल का औसत रहा। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि को प्रतिबिंबित करते हुए, पेट्रोल और डीजल के लिए पंप की कीमतें जनवरी के स्तर से अब तक फरवरी में लगभग ₹2 प्रति लीटर बढ़कर क्रमशः लगभग ₹90 प्रति लीटर और ₹81 प्रति लीटर हो गई हैं। मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष करों

चार्ट 27: डीसीए आवश्यक वस्तु कीमतें



सारणी 5: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें (चार प्रमुख महानगरों का औसत)

मद	युनिट	घरेलू कीमतें			महीना-दर महीना (प्रतिशत)	
		फर-20	जन-21	फर-21 ^	जन-21	फर-21
पेट्रोल	₹/लीटर	75.01	87.57	89.60	1.5	2.3
डीजल	₹/लीटर	67.35	78.97	81.11	1.8	2.7
केरोसीन	₹/लीटर	29.51	25.83	27.36	11.3	5.9
एलपीजी	₹/सिलेंडर	866.25	704.63	729.63	0.0	3.5

^: 1-12 फरवरी 2021 की अवधि के लिए

टिप्पणी: चार प्रमुख महानगरों (चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा लगाए जाने वाले कीमतों का औसत।

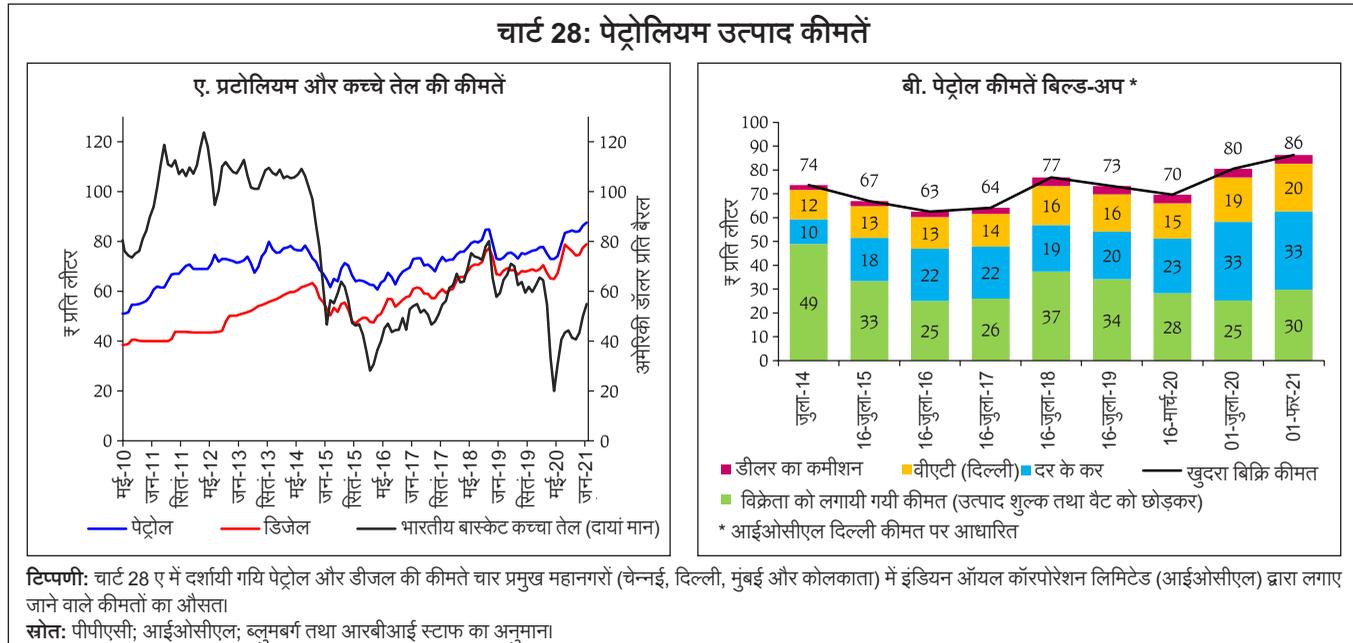
स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

में बढ़ोतरी के कारण यह घरेलू पंप की कीमतों के लिए एक ऐतिहासिक उच्चांक है। घरेलू केरोसीन और एलपीजी की कीमतों में भी फरवरी 2021 में वृद्धि दर्ज की गई (सारणी 5)।

कच्चे तेल की कीमतें 2014 के मध्य में लगभग 110 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से गिरकर अप्रैल 2020 में लगभग 20 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर पर आ गई थीं, जो जनवरी 2021 में 55 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ी थी

(चार्ट 28ए)। इस अवधि के दौरान, अंतरराष्ट्रीय पेट्रोल की कीमतों (विनिमय दर⁹ और शिपिंग लागत के लेखांकन के बाद) में भी लगभग ₹19 प्रति लीटर की गिरावट आई। हालांकि, पेट्रोल की पंप कीमतें (दिल्ली की कीमत) जुलाई 2014 के लगभग ₹ 74 प्रति लीटर से बढ़कर फरवरी 2021 की शुरुआत में ₹86 रुपये प्रति लीटर हो गई, लगभग प्रति लीटर ₹12 रुपये की वृद्धि है, जो पेट्रोल पर केंद्रीय करों में ₹23 रुपये प्रति लीटर और राज्य वैट (दिल्ली) में ₹8 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के कारण है (चार्ट 28बी)। पेट्रोल पंप की कीमतों (दिल्ली) में उत्पाद शुल्क और वैट जुलाई 2014 के लगभग 30 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2021 की शुरुआत में 60 प्रतिशत हो गई। नतीजतन, समय के साथ, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के अनुरूप घरेलू पेट्रोल पंप की उच्च कीमतों में कमी आयी। सितंबर 2013 में कच्चे तेल की कीमत ₹80 रुपये प्रति लीटर थी, जो जून-अगस्त 2018 के दौरान 73 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल और जून 2020 में 41 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। हेडलाइन मुद्रास्फीति में सीपीआई पेट्रोल (सीपीआई में 2.2 प्रतिशत भार के साथ) का प्रत्यक्ष योगदान जुलाई 2014 के 1.6 प्रतिशत से जनवरी 2021 में 4.8 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 28: पेट्रोलियम उत्पाद कीमतें



⁹ जुलाई 2014 में अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज लगभग ₹ 60 प्रति अमेरिकी डॉलर था जो अप्रैल 2020 में लगभग ₹ 76 प्रति अमेरिकी डॉलर हुआ और उसके बाद जनवरी 2021 में लगभग ₹ 73 प्रति अमेरिकी डॉलर तक मूल्य वृद्धि हुई।

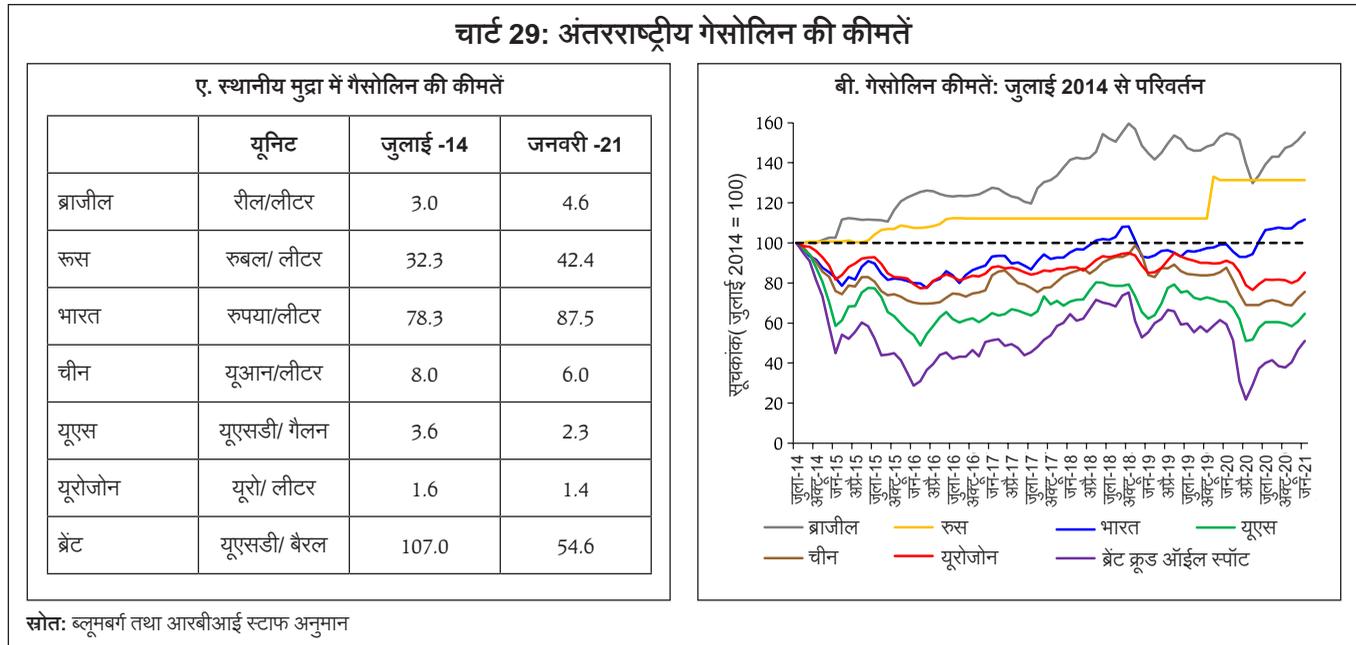
आगे बढ़ते हुए, बंपर खरीफ फसल के साथ-साथ अच्छी रबी फसल की संभावना से अनाज मुद्रास्फीति पर काबू पा सकते हैं। रबी फसल की आवक शुरू होने के साथ ही प्याज के दाम भी बढ़ने शुरू हो सकते हैं। हालांकि, खाद्य तेल में देखा गया मूल्य दबाव अंतरराष्ट्रीय कीमतों में नरमी पर निर्भर है। महंगाई का दबाव और बढ़ने की संभावना है। मूल मुद्रास्फीति के दबाव के बने रहने की संभावना है क्योंकि लागतजन्य दबाव और तेज हो गया है। रिकॉर्ड स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ औद्योगिक कच्चे माल और अंतवर्ती की लागत में व्यापक वृद्धि, निवेश कीमतों में वृद्धि को फर्मों द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं तक बढ़ाने का खतरा है, खासकर जब तक आर्थिक बहाली में गति मिले और गतिविधियां पूर्व-कोविड स्तर तक सामान्य हो।

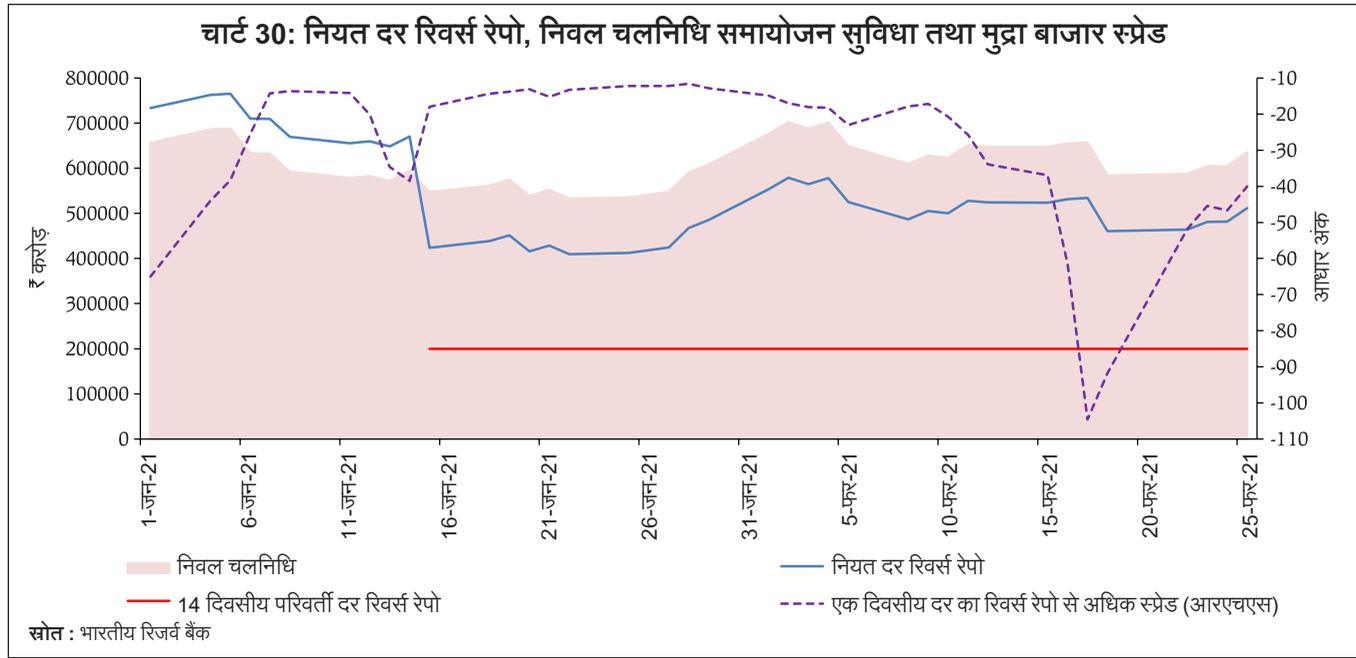
एक क्रॉस-कंट्री परिप्रेक्ष्य में, भारत ने 2010 के दशक की दूसरी छमाही में सबसे कम पास-थ्रू-आउट देखा था जब कच्चे तेल की कीमतों में काफी नरमी आई थी। लॉकडाउन के बाद अतिरिक्त करों के कारण, अंतरराष्ट्रीय पेट्रोल की कीमतें और बढ़ गयी तथा भारतीय उपभोक्ता द्वारा दी गयी पंप कीमतें दुनिया में सबसे अधिक रही (चार्ट 29)।

IV. वित्तीय स्थिति

एलएएफ के तहत जनवरी 2021 में लगभग ₹5.95 लाख करोड़ रुपये और फरवरी 2021 में ₹6.40 लाख करोड़ रुपये (25 फरवरी तक) दैनिक निवल चलनिधि अवशोषण से प्रणालीगत चलनिधि बड़े अधिशेष के रूप में प्रस्तुत किया गया। चलनिधि प्रबंधन परिचालन के क्रमिक सामान्यीकरण के भाग के रूप में, रिजर्व बैंक ने सामान्यीकरण शुरू करने के लिए 15 जनवरी को किए गए समान परिचालन के अनुक्रम में 29 जनवरी 2021 को ₹2 लाख करोड़ रुपये की राशि की और एक परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी आयोजित की। दूसरी नीलामी को अच्छा प्रतिसाद मिला, जिसमें बोली लगाने के प्रस्ताव ₹2 लाख करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि से 1.5 गुना अधिक थे। इस तरह की दो और नीलामियां 12 और 26 फरवरी 2021 को आयोजित की गई थीं, जिन्हें अच्छा प्रतिसाद मिला। 15 जनवरी 2021 से स्थिर दर रिवर्स रेपो के माध्यम से अवशोषित चलनिधि 16-29 जनवरी 2021 के दौरान ₹4.33 लाख करोड़ रुपये के पाक्षिक औसत से बढ़कर 30 जनवरी-25 फरवरी के दौरान ₹5.21 लाख करोड़ रुपये हो गई है (चार्ट 30)।

चार्ट 29: अंतरराष्ट्रीय गैसोलिन की कीमतें



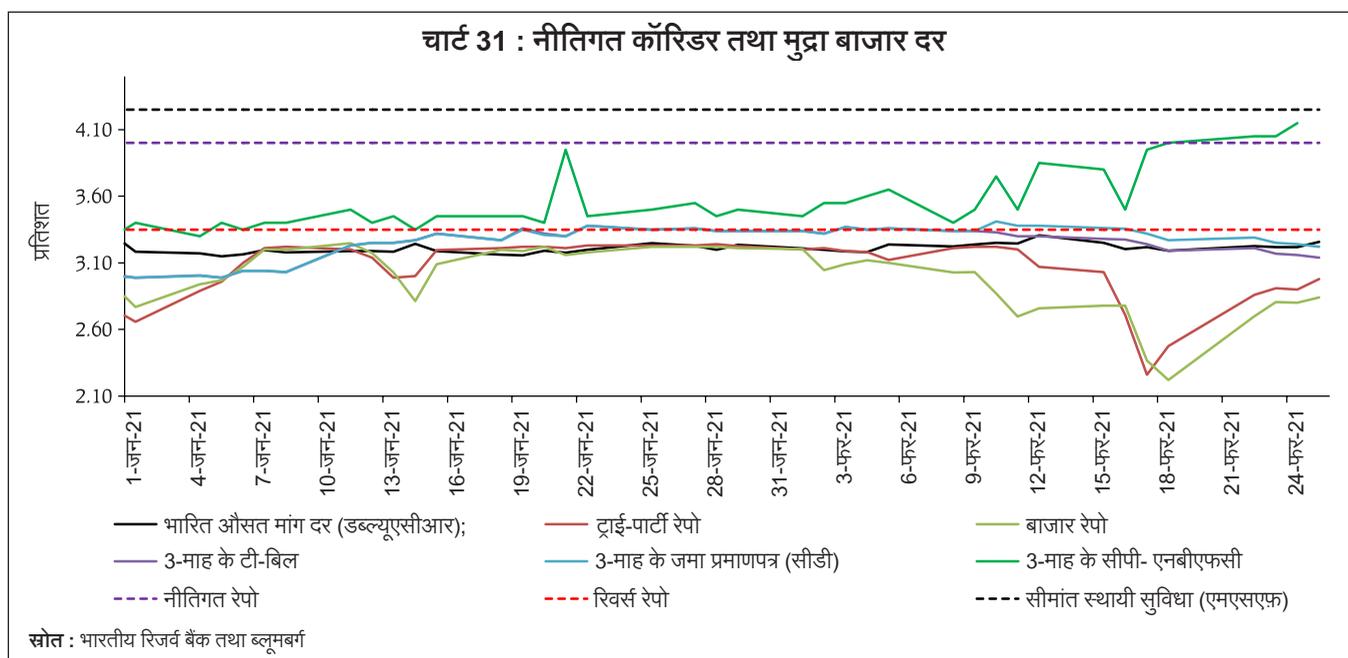


प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पालन करते हुए रिजर्व बैंक ने 21 जनवरी 2021 को एक खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) का संचालन किया जिससे प्रणाली में ₹10000 करोड़ की स्थायी चलनिधि डाल दी गई। बैंक ने 7 तथा 14 जनवरी 2021 को दो विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट) संचालित किए जिनमें प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री की गई। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने 5 फरवरी 2021 को अतिरिक्त चलनिधि उपाय किए जिनमें (i) मांग के अनुसार प्राप्य (ऑन टैप) लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचलन (टीएलटीआरओ) योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दबावग्रस्त क्षेत्रों को वर्धित उधार देने के लिए बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार देने की अनुमति (ii) गैर-विघटनकारी तरीके से दो चरणों में नकद आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) की क्रमिक बहाली की घोषणा की जिसके अनुसार 27 मार्च, 2021 से यह एनडीटीएल का 3.5 प्रतिशत और 22 मई, 2021 से 4.0 प्रतिशत होगा; और (iii) निवल मांग तथा मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.0 प्रतिशत तक एसएलआर को घटाकर, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत निधियों का लाभ उठाने की सुविधा 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाना शामिल था। रिजर्व बैंक ने अनुकूल वित्तीय स्थिति को बढ़ावा देने के लिए 10 फरवरी 2021 को ₹20,000 करोड़ की वर्धित राशि के लिए एक ओएमओ खरीद

नीलामी तथा 25 फरवरी 2021 को विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट) भी संचालित किए।

अतिरिक्त चलनिधि को प्रतिबिंबित करते हुए एक दिवसीय मुद्रा बाजार दर अर्थात् भारत औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर), ट्राई-पार्टी रेपो दर तथा बाजार रेपो दर का औसत रूप से जनवरी में क्रमशः 16 आधार अंक, 22 आधार अंक, तथा 23 आधार अंक तथा फरवरी में (25 फरवरी 2021 तक) क्रमशः 12 आधार अंक, 35 आधार अंक तथा 50 आधार अंक रिवर्स रेपो दर के नीचे रहना जारी रहा। गैर- बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी की गए 3-माह के वाणिज्यिक पेपर (सीपी), 3-माह के टी-बिल तथा 3-माह के जमा प्रमाणपत्र (सीडी) की दरें दो महीने के अंतराल के बाद जनवरी 2021 में रिवर्स रेपो दर से अधिक थी (चार्ट 31)। सीपी (एनबीएफसी) दर को छोड़कर उपर्युक्त दर फरवरी 2021 में रिवर्स रेपो दर से काम हो गए जो कि अतिरिक्त चलनिधि को प्रतिबिंबित करते हैं।

कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्रतिफल स्थिर रहे और रेटिंग स्पेक्ट्रम तथा जारीकर्ता श्रेणियों के बीच के अंतर कम हो गए जो कि कम होते हुए जोखिम प्रीमियम तथा अनुकूल नीतिगत परिवेश को दर्शाते हैं। निम्नलिखित अर्थात्, (i) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं (एफआई), (ii) कॉर्पोरेट, तथा (iii) एनबीएफसी द्वारा जारी 3-वर्ष के AAA रेटेड कॉर्पोरेट



बॉन्ड का तदनुरूपी परिपक्वता वाले सरकारी बॉन्डों के प्रतिफल से अधिक औसत अंतर जनवरी में क्रमशः 17 आधार अंक, 14 आधार अंक तथा 21 आधार अंकों से कम हो गया। इन संस्थाओं द्वारा जारी की गए 3-वर्ष के बीबीबी रेटे बॉन्डों – सबसे निम्नतर रेट की गए निवेश ग्रेड बॉन्ड- पर स्प्रेड भी क्रमशः 25 आधार अंक, 12 आधार अंक तथा 19 आधार अंकों से कम हो गया जो घटती हुई जोखिम विमुखता तथा चलनिधि से समृद्ध प्रणाली को दर्शाते हैं (सारणी 6)।

सारणी 6: कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल और स्प्रेड

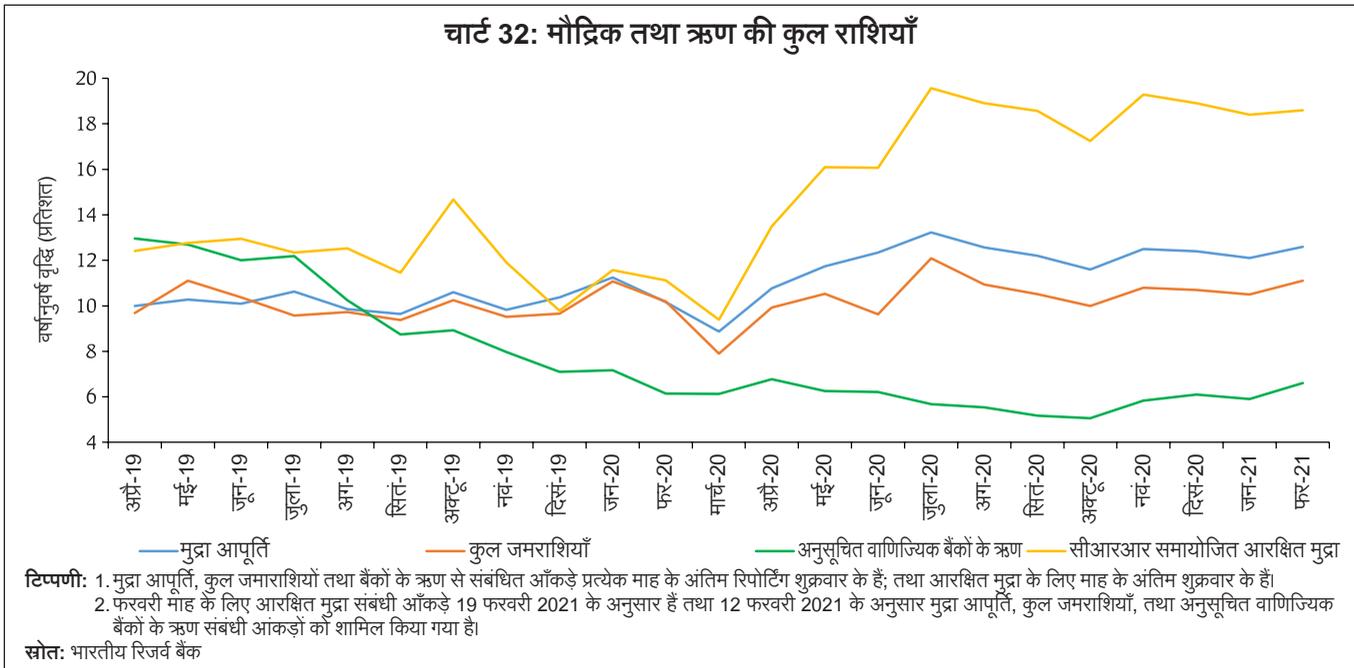
जारीकर्ता	रेटिंग	प्रतिफल			स्प्रेड		
		दिसं-20	जन-21	घट-बढ़	दिसं-20	जन-21	घट-बढ़
		(प्रतिशत)	(आधार अंक)				
पीएसयू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं	एए	4.89	4.96	7	43	26	-17
	एए	5.56	5.62	6	114	92	-22
	बीबीबी-	8.76	8.75	-1	430	405	-25
कॉर्पोरेट	एए	4.76	4.85	9	30	16	-14
	एए	5.62	5.74	12	116	105	-11
	बीबीबी-	9.57	9.69	12	512	500	-12
एनबीएफसी	एए	4.94	4.96	2	48	27	-21
	एए	6.28	6.34	6	182	164	-22
	बीबीबी-	10.56	10.62	6	611	592	-19

टिप्पण: प्रतिफल तथा स्प्रेड माह के औसत हैं।

स्रोत: एफआईएमएमडीए

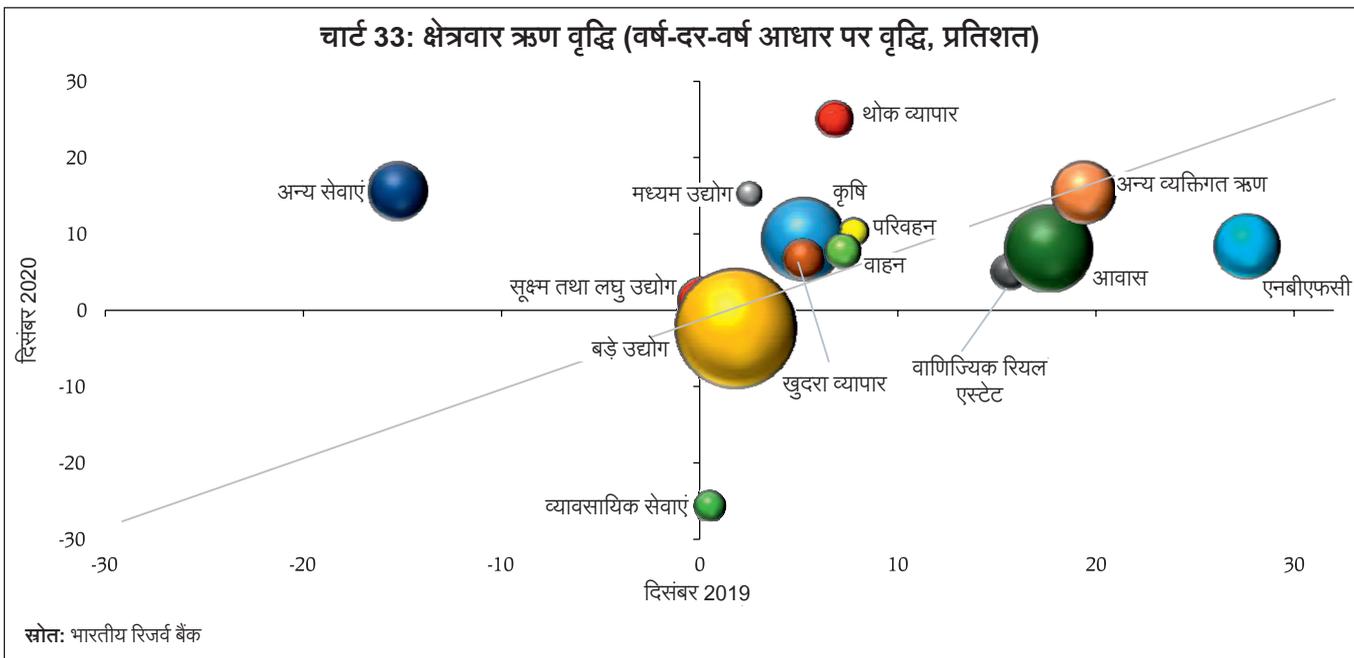
चलनिधि के व्यापक उपाय भी प्रणाली में मौद्रिक तथा ऋण स्थितियों के सुकर होने के संकेत देते हैं। आरक्षित मुद्रा (आरएम) जिसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित किया गया था, में वर्ष-दर-वर्ष (19 फरवरी 2021) (चार्ट 32) आधार पर 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण था संचलनगत मुद्रा (CiC) में 20.3 प्रतिशत की वृद्धि (एक साल पूर्व 11.9 प्रतिशत)। मुद्रा में उच्च विस्तार सहित समग्र जमाराशियों में 11.1 प्रतिशत (12 फरवरी 2021) पर हो रही वृद्धि के कारण मुद्रा आपूर्ति (M3) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर (एक साल पूर्व 9.5 प्रतिशत) 12.6 प्रतिशत विस्तार हुआ। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी)द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में 12 फरवरी 2021 को 6.6 प्रतिशत (एक साल पूर्व 6.4 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई।

समग्र ऋण वृद्धि में होने वाली क्रमिक लेकिन स्थिर बहाली के भीतर कुछ उज्ज्वल बिन्दु उभर रहे हैं। दिसंबर 2020 में कृषि, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों, परिवहन सेवाओं, थोक व्यापार, खुदरा व्यापार तथा अन्य सेवाओं के लिए ऋण तथा वाहनों की खरीद के लिए व्यक्तिगत ऋण जो कि कुल ऋण का 35 प्रतिशत थे, में तेज गति से वृद्धि हुई। व्यक्तिगत ऋण खंड के दूसरे सबसे बड़े घटक, अन्य व्यक्तिगत ऋण (10), में दिसंबर 2020 में 15



प्रतिशत की तेज गति से वृद्धि हुई। बड़े उद्योगों को बैंक ऋण की मात्रा कम ही रही, लेकिन इन में से बहुत सारे उधारकर्ता, विशेष रूप से उच्च रेटिंग वाले उधारकर्ता प्रचलित कम ब्याज दर वाले दौर का लाभ उठाने तथा पिछले उच्च लागत वाले कर्ज को समाप्त करने के लिए बॉन्डों, डिबेन्चर तथा अन्य बाजार आधारित लिखतों के माध्यम से निधियाँ जुटा रहे हैं। व्यावसायिक सेवाओं

के लिए ऋण भी कम थे। गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक ऋण भी एक वर्ष पूर्व की 28 प्रतिशत (चार्ट 33) की सुदृढ़ वृद्धि की तुलना में दिसंबर 2020 में 8 प्रतिशत तक घट गया। हालही में टीएलटीआरओ ऑन टैप योजना के अंतर्गत बैंकों को एनबीएफसी को उधार देने के लिए अनुमति देने की पहल से दबावग्रस्त क्षेत्रों को ऋण में वृद्धि होने की अपेक्षा है।



¹⁰ अन्य व्यक्तिगत ऋणों में अन्य बातों के साथ साथ घरेलू उपभोग, चिकित्सकीय व्यय, यात्रा, ब्याह तथा अन्य सामाजिक समारोह शामिल हैं।

ऋण बाजार में, एससीबी की 1-वर्षीय माध्यिक निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत में 91 बीपीएस (मार्च 2020 से जनवरी 2021 तक) की गिरावट आई है। माध्यिक मीयादी जमा दर में भी 146 बीपीएस की कमी हुई। निधि की लागत में कमी इसके उधार दरों की ओर संचरण के लिए अच्छा संकेत है (सारणी 7)।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) पर प्रतिफल दशकीय निम्न स्तर पर ट्रेड करते रहे, जिसमें अधिशेष तरलता और कोविड-19 के मद्देनजर रिजर्व द्वारा उठाए गए कदमों से सहायता मिली। तथापि नए 10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क (5.85 जीएस 2030) और पुराने 10-वर्षीय जी-सेकंड बेंचमार्क (5.77 जीएस 2030) पर प्रतिफल क्षणिक दबाव में आया, जो जनवरी 2021 के अंत में क्रमशः 5.91 प्रतिशत और 5.95 प्रतिशत पर बंद हुआ। अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में बढ़ोतरी, माह के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और केंद्रीय बजट में 2021-22 के लिए ₹12 लाख की सकल बाजार ऋण योजना और साथ ही 2020-21 की शेष अवधि के लिए ₹80,000 करोड़ के अतिरिक्त उधार की घोषणा से बाजार की धारणा दबाव में रही। बाद में प्रतिफल सहज हुए, जिसके कारण थे: (i) रिजर्व बैंक द्वारा 10 फरवरी 2021 को ₹20,000 करोड़ की बढ़ी हुई राशि के लिए ओएमओ

खरीद की घोषणा और संचालन, जिसमें से अधिकतर खरीद 10-वर्षीय खंड के लिए थी; (ii) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में एनडीटीएल के 22 प्रतिशत की बढ़त की छूट को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाना; (iii) खुदरा निवेशकों को सीधे रिजर्व बैंक ('रिटेल डायरेक्ट') के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति बाजार- प्राथमिक और द्वितीयक दोनों- तक ऑनलाइन पहुंच देना), जिससे निवेशक आधार में बढ़ोतरी और घरेलू बचत के दोहन से सरकार के ऋण लेने की लागत कम हो सकती है; तथा (iv) अनुकूल वित्तपोषण स्थितियों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त तरलता प्रदान करने के लिए स्पष्ट भावी मार्गदर्शना। इन उपायों से प्रोत्साहित होकर, नए और पुराने 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल, केंद्रीय बजट के बाद आई तेजी के बाद, 11 फरवरी, 2021 के अनुसार क्रमशः 17 बीपीएस और 13 बीपीएस कम हो गए (चार्ट 34 और 35)। तथापि इसके बाद, ये बेंचमार्क प्रतिफल फरवरी 2021 के अंत में क्रमशः 6.23 प्रतिशत और 6.32 प्रतिशत तक चढ़ गए, जो मुख्य रूप से वैश्विक कारकों जैसे कि कड़े होते अमेरिकी प्रतिफल और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण है। जैसा कि इस आलेख में पहले बताया गया है आरबीआई ने 25 फरवरी को ₹10,000 करोड़ का विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट) चलाया जिसे खरीद पक्ष में 4.9 और बिक्री पक्ष में 3.3 के नीलामी- कवर अनुपात के साथ काफी

सारणी 7: रेपो दर से बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंक)

अवधि	रेपो दर	मीयादी जमा दर		उधार दर		
		मध्यम अवधि जमा दर	डब्ल्यू-एडीटीडीआर	1-वर्ष माध्यिक एमसी-एलआर	डब्ल्यू-एएलआर-बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यू-एएलआर-नए रुपया ऋण
फर 2019 - सितं 2019	-110	-9	-7	-30	2	-40
अक्टू 2019 - जन 2021*	-140	-175	-127	-118	-91	-144
मार्च 2020 - जन 2021*	-115	-146	-88	-91	-73	-113
फर 2019 - जन 2021*	-250	-209	-134	-145	-89	-184

*: डब्ल्यूएएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर पर नवीनतम डेटा दिसंबर 2020 से संबंधित है।

डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर।

डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू अवधि जमा दर;

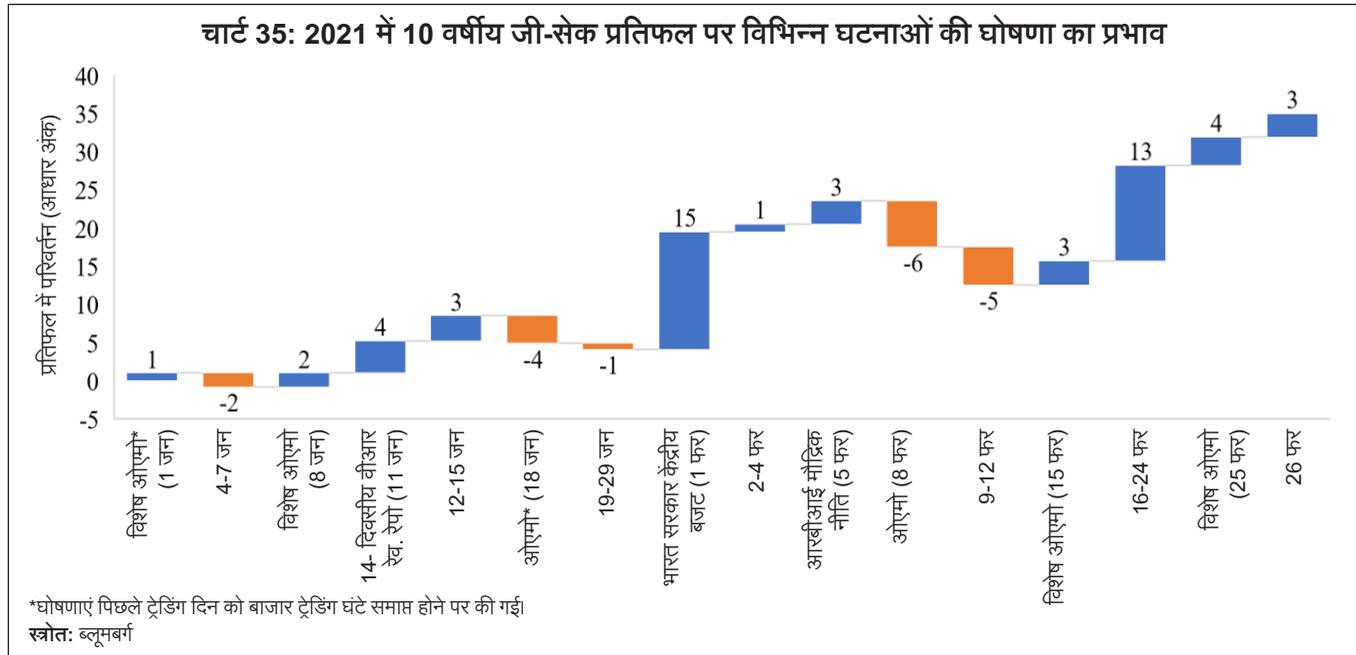
एमसीएलआर: निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दरें।

स्रोत: आरबीआई

चार्ट 34: 10 वर्षीय बेंचमार्क जी-सेक प्रतिफल



स्रोत: सीसीआईएल और ब्लूमबर्ग



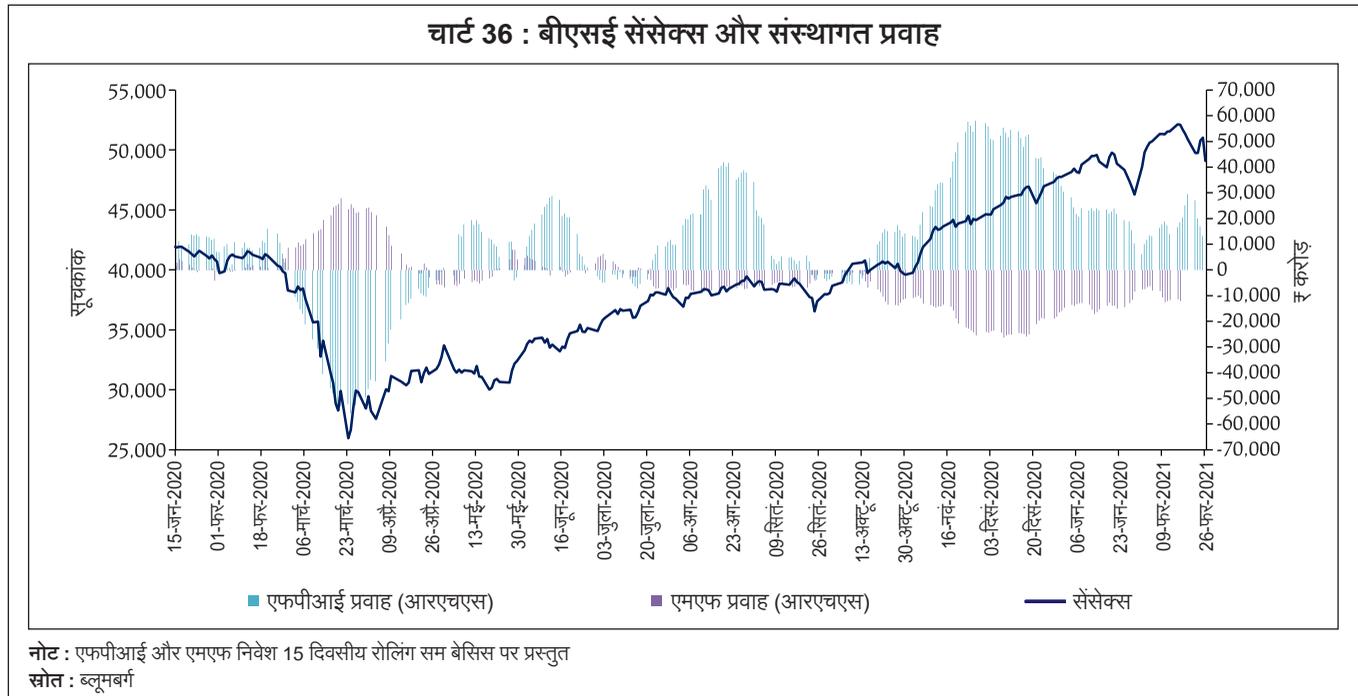
अच्छी प्रतिक्रिया मिली। अपने उपायों को जारी रखते हुए ₹15,000 करोड़ की बढ़ाई गई राशि के लिए ऐसा एक और परिचालन 4 मार्च, 2021 को किया जाना है।

भारतीय इक्विटी बाजार ने जनवरी 2021 में नई उंचाईयां छुईं, जब माह के अंत में सभी लाभों का मिलान करने के बाद हानि दर्ज करने से पहले, बीएसई सेंसेक्स ने इंट्रा-डे ट्रेड में थोड़े समय के लिए ऐतिहासिक 50,000 अंक को पार किया (21, जनवरी 2021 को)। प्रारंभ में, इक्विटी बाजार अच्छी खबरों के बल पर बढ़ गया - दिसंबर 2020 के लिए विनिर्माण पीएमआई में विस्तार; देश में दो टीकों और उनके रोलआउट के लिए सरकार का अनुमोदन; और 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए कॉर्पोरेट आय परिणामों के प्रति आशावाद। माह के अंत तक यह गति उलट गई जब अमेरिका में खुदरा विक्रेताओं द्वारा सट्टे की ट्रेडिंग और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा बिकवाली के कारण उत्पन्न हुए कमजोर वैश्विक संकेतों पर बाजार अस्थिर हुआ।

फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि भारत के बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स ने केंद्रीय बजट के बाद अपनी अब तक की सबसे तीव्र बढ़त (निश्चित रूप में) दर्ज की, जबकि वित्त मंत्री ने करों में बिना

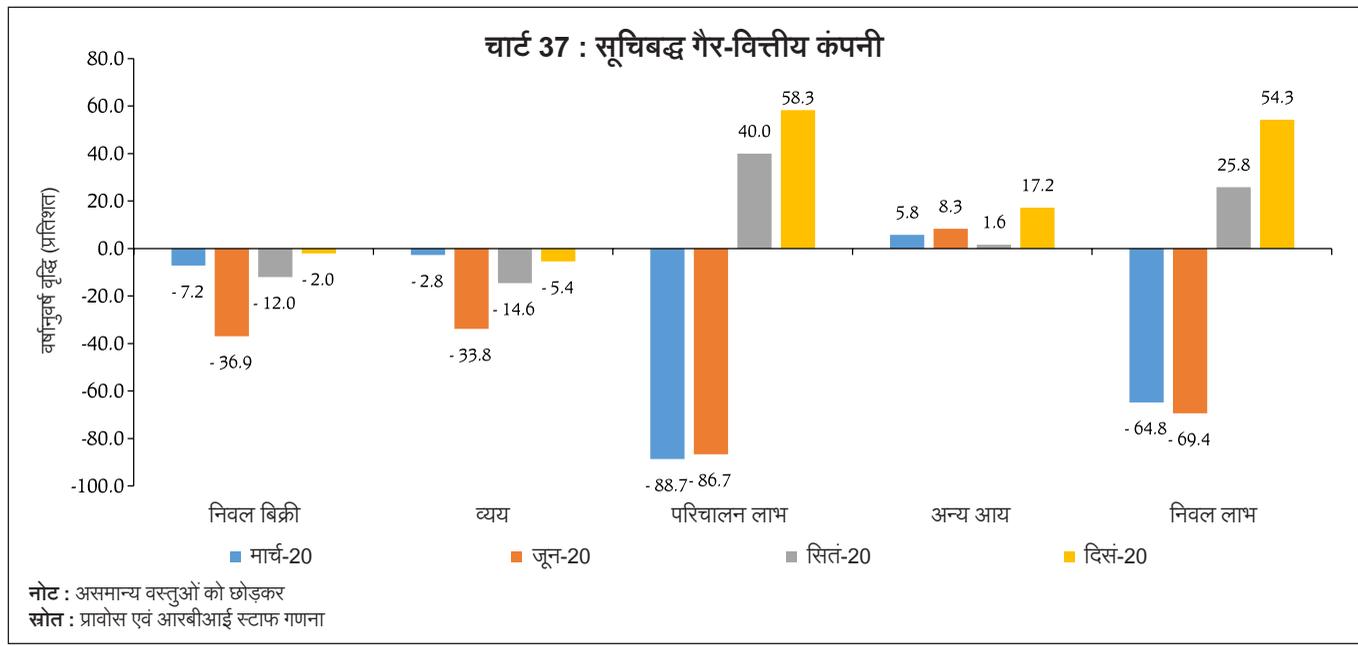
किसी बड़े बदलाव के आर्थिक पुनरुद्धार को प्रोत्साहित करने और सभी क्षेत्रों में खर्च को बढ़ावा देने के लिए उपायों की घोषणा की। 1 फरवरी 2021 को सेन्सेक्स 2,315 अंकों (5 प्रतिशत) से बढ़कर 48,601 पर बंद हुआ (चार्ट 36)। स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं, जिसमें अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के प्रबंधन के लिए एक आस्ति पुनर्चना कंपनी का गठन शामिल है, पीएसयू का रणनीतिक विनिवेश, दो सरकारी बैंकों और एक जनरल बीमा कंपनी का निजीकरण, और बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा 74 प्रतिशत तक बढ़त के कारण निवेशक धारणा बेहतर हुई। पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि से समग्र धारणा में तेजी आई।

फरवरी 2021 में बीएसई-सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण ने ₹200 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा पहली बार पार किया, जो निरंतर तेजी द्वारा निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण धन निर्माण दर्शाता है। देश का बाजार पूंजीकरण के प्रति जीडीपी अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक है। वस्तुतः, जनवरी 2021 के बाद से, दुनिया के शीर्ष 10 बाजारों में केवल हांगकांग को छोड़कर भारत के इक्विटी बाजारों में सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ। भारत का शेयर बाजार अब बाजार मूल्य के मामले में, दुनिया में आठवां सबसे बड़ा बाजार हो गया है।



भारतीय सूचीबद्ध कॉरपोरेट द्वारा 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए घोषित आय परिणाम आर्थिक गतिविधि की मजबूत वापसी का प्रमाण देता है। परिणाम घोषित करने वाली 3,014 गैर-वित्तीय सूचीबद्ध कंपनियों के लिए हालांकि तीसरी तिमाही¹¹ में निवल बिक्री वृद्धि में संकुचन बना

रहा, लेकिन पूर्ववर्ती तीन-तिमाहियों की तुलना में इसकी गति मध्यम रही। फिर भी, कम ब्याज खर्च के कारण कच्चे माल की लागत और लागत बचत में गिरावट के कारण बिक्री की तुलना में व्यय तेजी से गिरा और परिचालन लाभ में इजाफा हुआ (चार्ट 37)।



¹¹ तीसरी तिमाही : 2020-21 के दौरान रिफाइनिंग सेक्टर को छोड़कर बाकी गैर-वित्तीय कंपनी की निवल बिक्री में, दूसरी तिमाही : 2020-21 के दौरान 8.4% के संकुचन के बाद, साल-दर-साल 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारणी 8 : क्षेत्रवार कॉरपोरेट प्रदर्शन

चयनित सेक्टर	निवल बिक्री वृद्धि (साल-दर-साल, प्रतिशत)				परिचालन लाभ वृद्धि (साल-दर-साल, प्रतिशत)				निवल लाभ वृद्धि (साल-दर-साल, प्रतिशत)			
	मार्च-20	जून-20	सितं-20	दिसं-20	मार्च-20	जून-20	सितं-20	दिसं-20	मार्च-20	जून-20	सितं-20	दिसं-20
आईटी	7.4	4.3	4.5	6.0	20.2	12.5	19.0	24.1	15.4	6.3	12.5	18.4
रिफाइनिंग	-5.0	-49.2	-25.2	-17.4	-170.8	-37.8	65.2	27.5	-143.5	-6.1	85.5	29.2
एफएमसीजी	0.2	-6.4	7.5	6.9	-16.7	-13.1	16.2	12.7	-20.2	-2.1	7.4	8.1
फार्मास्युटिकॉल	5.5	5.5	9.8	10.2	2.1	28.0	38.8	45.1	9.8	16.2	33.9	63.7
स्टील	-18.7	-39.1	10.5	16.8	-28.9	-401.3	n.m.	n.m.	46.3	-604.3	34.2	n.m.
ऑटो एण्ड ऑटो एन्सिलियरिज	-17.2	-65.2	3.4	20.3	-55.0	-198.0	8.5	56.7	-37.5	-157.6	-11.3	50.8
सिमेंट	-11.8	-33.4	4.6	11.2	5.3	-44.8	83.9	107.4	12.7	-36.9	70.6	111.7

नोट : असमान्य वस्तुओं को छोड़कर, उल्लिखित नहीं का अर्थ महत्वपूर्ण नहीं
स्रोत : प्रावोस एवं आरबीआई स्टाफ गणना

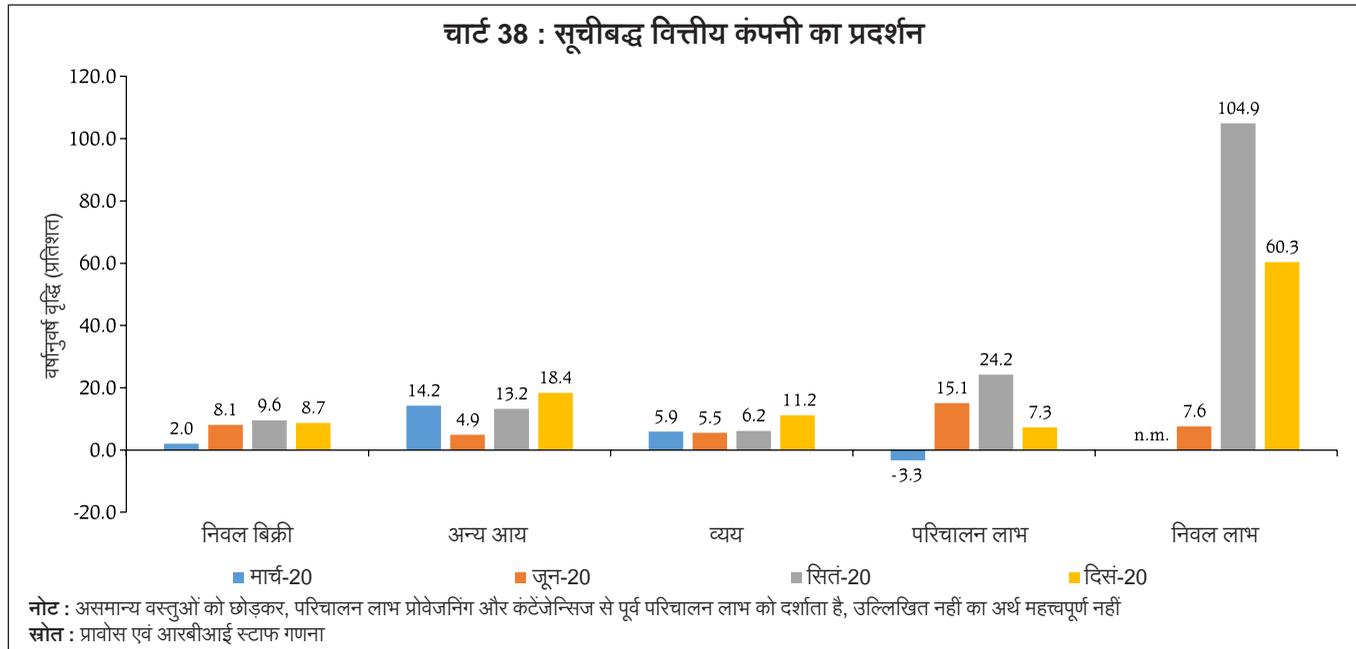
गैर-वित्तीय क्षेत्र पर किए गए अलग-अलग विश्लेषण से पता चलता है कि ऑटो, स्टील और सीमेंट जैसे आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान प्रभावशाली प्रदर्शन दर्ज किया गया, जैसा कि पहले शुरू हुआ था (सारणी 8)। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की कंपनियों ने 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान पिछले कई वर्षों की तुलना में सबसे मजबूत तिमाही प्रदर्शन दर्ज करते हुए अपनी बिक्री में तेज वृद्धि की।

इसी प्रकार, भारत में 853 सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के) : 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान कमाई के परिणाम मजबूत प्रदर्शन का संकेत देते हैं (चार्ट 38)। निवल

बिक्री, जिसमें मुख्य रूप से ब्याज आय शामिल है, में स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अन्य आय, जिसमें परिसंपत्तियों और निवेश की बिक्री से लाभ / हानि जैसे प्रवाह शामिल हैं, तिमाही के दौरान पूंजी बाजार में तेजी बनाए रखा। कर्मचारी लागत में वृद्धि के कारण कुल व्यय में वृद्धि हुई, जिससे परिचालन लाभ में मामूली वृद्धि हुई। इसके अलावा, 2020-21 की तीसरी तिमाही में निजी बैंकों द्वारा भारी प्रावधान के कारण बेहतर आधार प्रभावों के कारण ऋण और अग्रिमों के प्रावधान में भारी गिरावट के कारण निवल लाभ में तेज वृद्धि हुई।

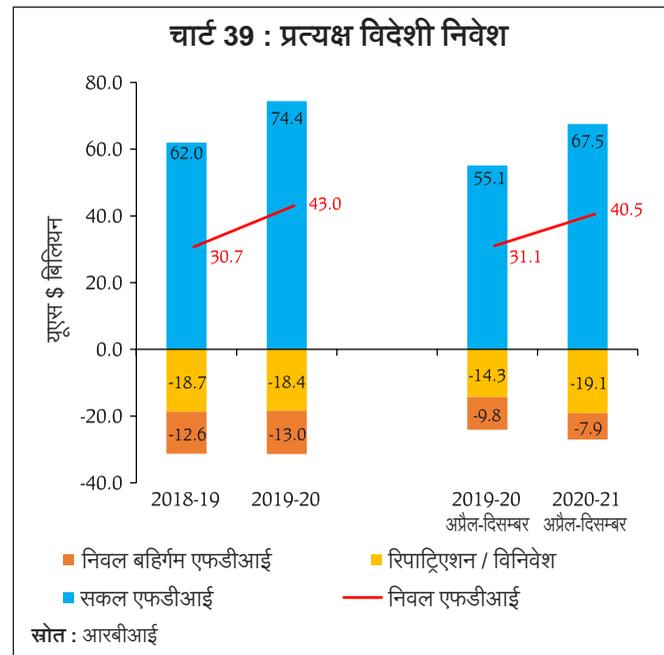
24 जनवरी को जारी यूएनसीटीएडी के 'इनवेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर' के अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के संबंध

चार्ट 38 : सूचीबद्ध वित्तीय कंपनी का प्रदर्शन

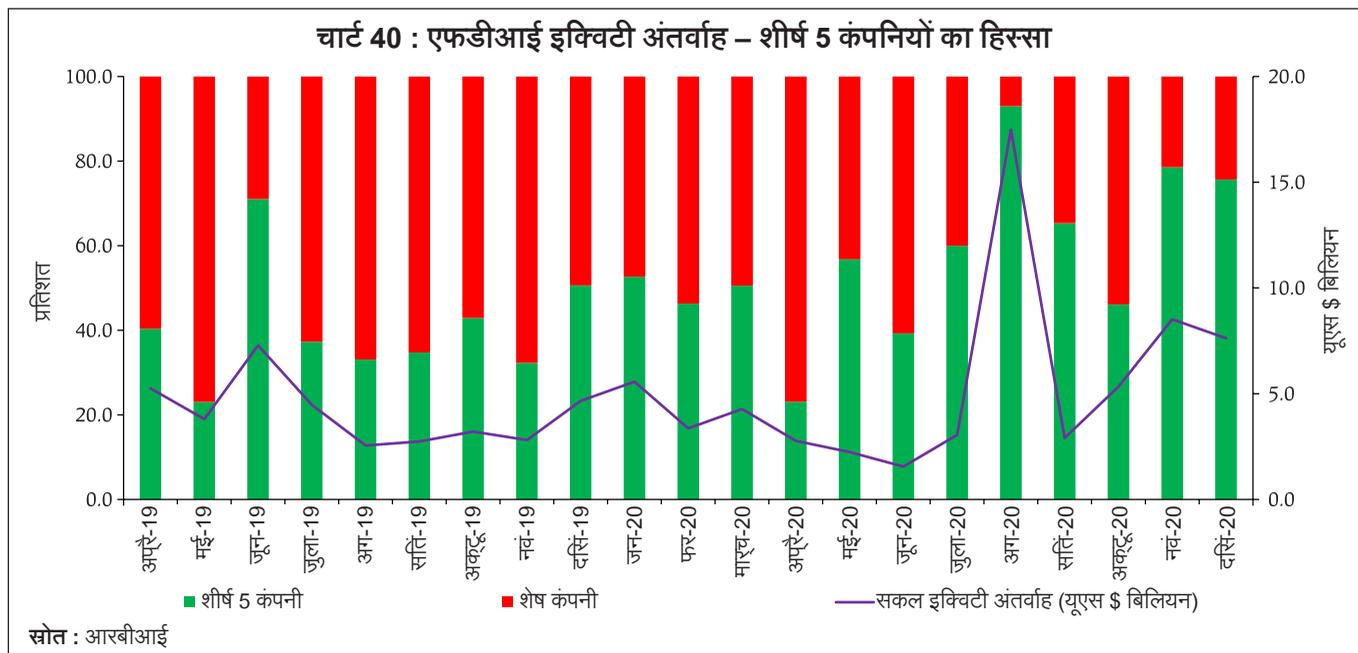


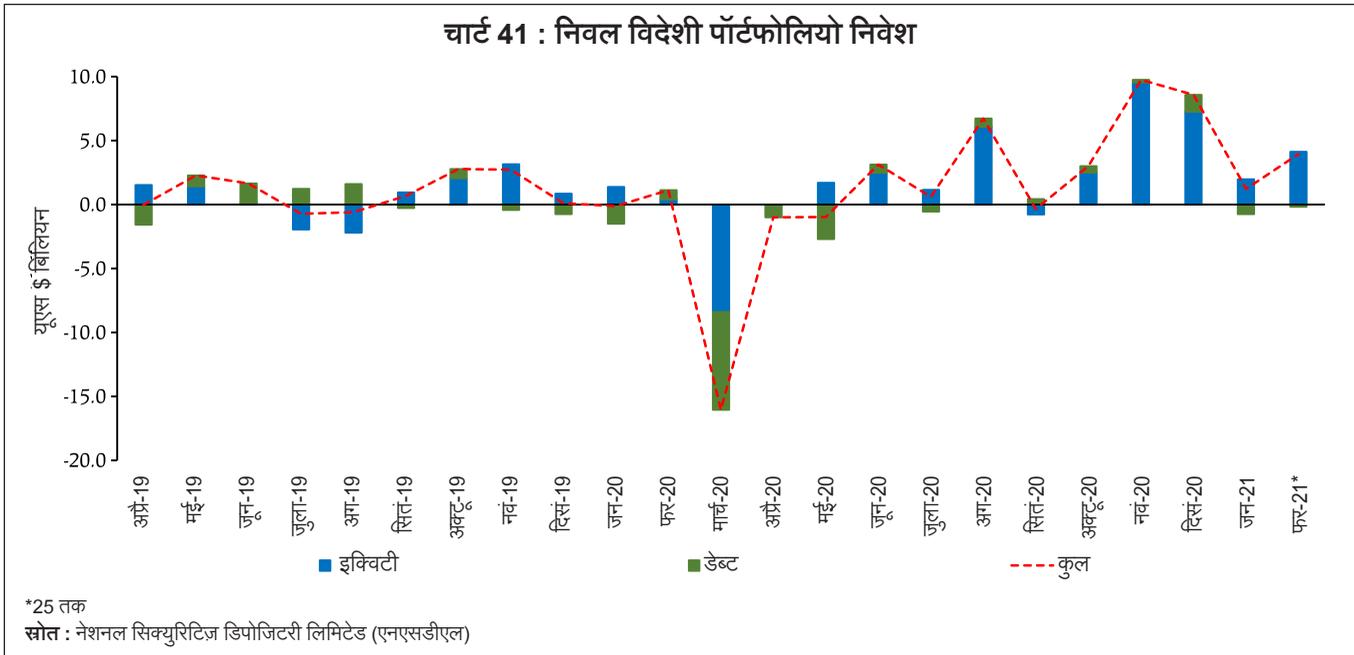
में भारत का स्थान अन्य की तुलना में उज्ज्वल बना रहा जबकि 2020 में साल दर साल वैश्विक प्रवाह 42% तक (यूएस \$ 859 बिलियन) गिर गया, जो 1990 के बाद से सबसे निचला स्तर है। भारत ने सार दर साल 13% (यूएस \$ 57 बिलियन) वृद्धि दर्ज की, बाकी देशों की तुलना में यह सबसे अधिक वृद्धि है और यह बढ़ोतरी डिजिटल क्षेत्र में प्रवाह के कारण रही। अगस्त-नवंबर 2020 के दौरान देखी गई तेजी के कारण दिसंबर 2020 में निवल एफडीआई प्रवाह मजबूत बना रहा। परिणामस्वरूप, निवल एफडीआई पिछले साल के यूएस \$ 31.1 बिलियन से अप्रैल-दिसंबर 2020 में बढ़कर यूएस \$ 40.5 बिलियन हो गया (चार्ट 39)। अगस्त-दिसंबर 2020 में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में वृद्धि काफी हद तक डिजिटल सेवाओं में हुए कुछ बड़े सौदों से प्रेरित थी(चार्ट 40)।

जनवरी 2021 में एफपीआई घरेलू पूंजी बाजार में निवल खरीदारों के रूप में बने रहे, हालांकि पिछले महीने की तुलना में इसमें मामूली कमी आई। जबकि अपेक्षा से बेहतर आय, आर्थिक पुनरुद्धार के संकेत, कोविड के घटते संक्रमण और चल रहे टीकाकरण अभियान ने एफपीआई को उत्साहित करना जारी रखा, फिर भी उन्होंने इस दौरान मुख्य रूप से बजट-पूर्व लाभ बुकिंग से अपने जोखिम को कम किया। जबकि यूएस \$ 1.2 बिलियन का निवल शुद्ध एफपीआई प्रवाह मुख्य रूप से यूएस \$ 2.0 बिलियन की इक्विटी खरीद से प्रेरित था, वे डेब्ट सेगमेंट



(चार्ट 41) में निवल विक्रेता बने रहे। जबकि जनवरी 2021 में एफपीआई प्रवाह में बजट-पूर्व अस्थिरता देखी गई, पूंजीगत व्यय और पीएसयू के निजीकरण पर अधिक ध्यान देने वाला सुधार परस्त बजट के कारण फरवरी 2021 में एफपीआई अंतर्वाह को बढ़ावा दिया। कुल मिलाकर 2020-21 में अबतक इक्विटी में एफपीआई का निवल निवेश यूएस \$ 36.1 बिलियन रहा जो, 2012-13 के बाद से अब तक का सर्वाधिक है।

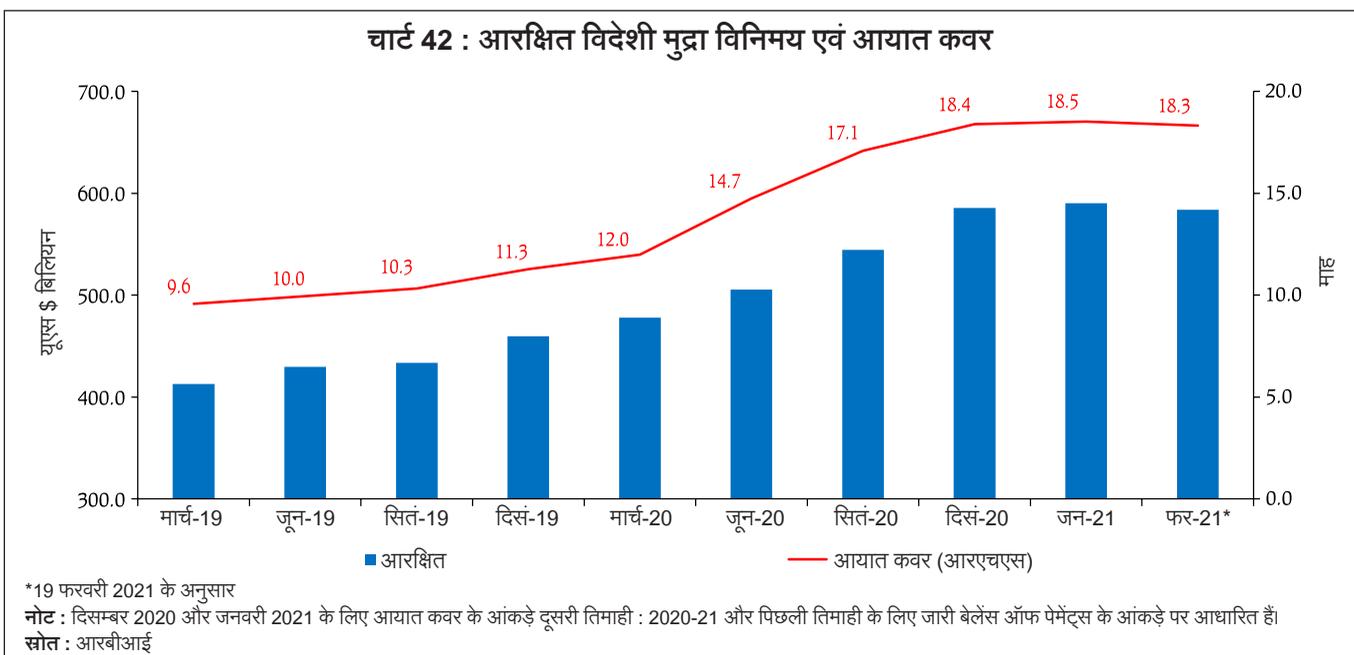


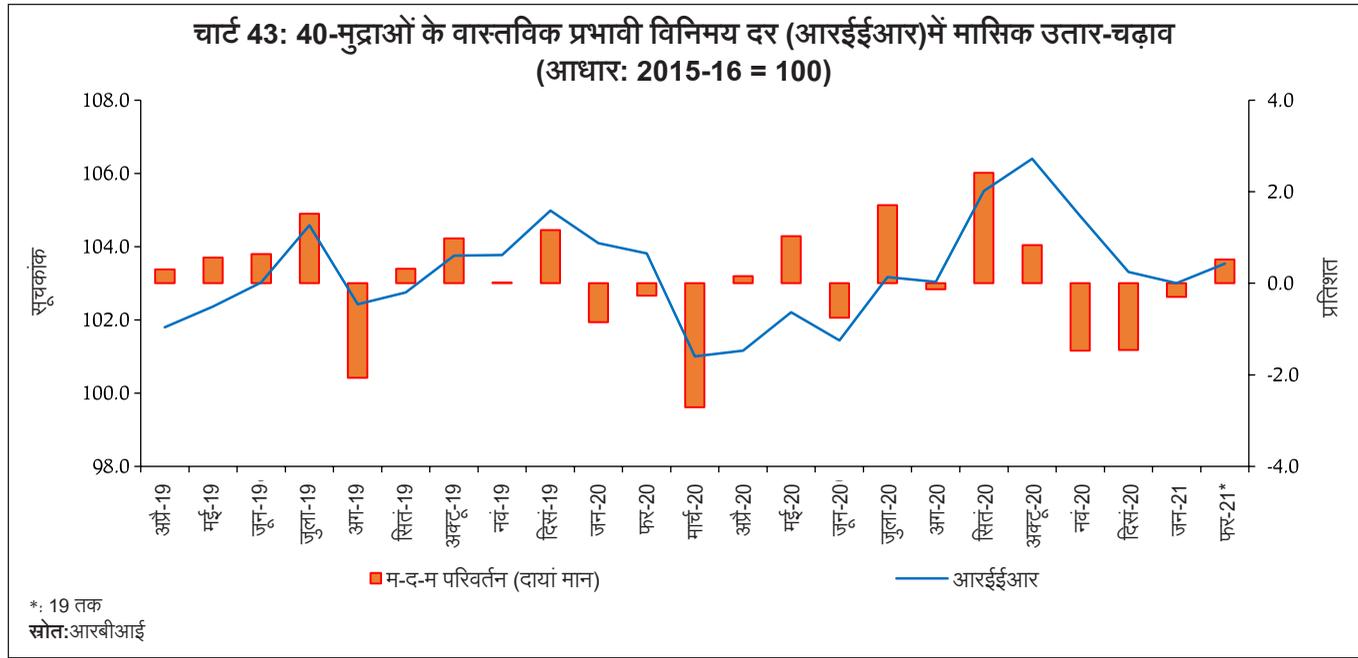


हाल के केंद्रीय बजट प्रस्ताव ने एफपीआई द्वारा रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्टों (InvITs) में डेब्ट वित्तपोषण की अनुमति दी है जिससे इन संस्थाओं के लिए धन के वैकल्पिक स्रोत का दरवाजा खुलेगा और इससे धन की लागत को कम करने के अलावा विदेशी निवेशकों के लिए भारत में अपेक्षाकृत सुरक्षित कर्ज निवेश विकल्प उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने कैपेक्स को तेज गति प्रदान करने

के संकेत के साथ, भारत द्वारा देश की सड़कों, बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऑफर किए जा रहे ग्रीन बॉन्ड ने विदेशी निवेशकों के बीच पहले से अधिक रुचि पैदा की है।

29 जनवरी 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार यूएस \$ 590.2 बिलियन के उच्च स्तर को छू गया और 19 फरवरी 2021 को यह यूएस \$ 583.9 बिलियन रहा (चार्ट 42)।





विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया (आईएनआर) लगातार मजबूत होता रहा और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और टीकाकरण रोल आउट के कारण एक महीने पहले फरवरी 2021 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.5 प्रतिशत अधिक रहा। मार्च 2020 के अंत में अपने स्तर से अधिक आईएनआर में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह पिछले साल सितंबर 2020 के शुरुआत में देखे गए स्तर से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹73.04 तक पहुंच गया। 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक के संदर्भ में, मार्च 2020 के अपने स्तर से अधिक फरवरी 2021 में आईएनआर में 2.5% की वृद्धि हुई।

भुगतान प्रणाली

भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र ने आर्थिक पुनरुद्धार में उत्प्रेरक के रूप में सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। तदनुसार, इसने जनवरी 2021 में पिछले महीने के थोक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में हुए शानदार प्रदर्शन के विकास गति को बनाए रखा। बाजार का अनुमान है कि 2025 तक, वित्तीय समावेशन और व्यापारियों के तेजी से

डिजिटलीकरण¹² का उपयोग करने की नीतियों के कारण भारत में डिजिटल भुगतान तीन गुना से अधिक ₹7,000 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है।

जनवरी 2021 के आते-आते, रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली के माध्यम से थोक लेन-देन की मात्रा में 14.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की दोहरी अंकों की वृद्धि जारी रही, जो इस महीने में बढ़कर 20.2 प्रतिशत से अधिक रही (टेबल 9)।

सारणी 9: वर्ष 2020-21 में लेन-देन का मूल्य

(₹ करोड में)

	आरटीजीएस	एनईएफटी	यूपीआई	आईएमपीएस
अप्रै-20	64.43.653	13.06.406	1,51,141	1,21,141
मई-20	70.41.869	14.81.750	2,18,392	1,69,402
जून-20	86.51.978	19.06.586	2,61,835	2,06,951
जुला-20	83.35.279	19.63.113	2,90,538	2,25,775
अग-20	72.92.380	19.30.552	2,98,308	2,35,137
सितं-20	94.89.066	21.65.515	3,29,032	2,48,662
अक्टू-20	84.96.046	22.35.389	3,86,107	2,74,645
नवं-20	79.87.655	22.18.252	3,90,999	2,76,459
दिसं-20	1,06,59,120	25,58,304	4,16,176	2,92,325
जन-21	91,70,162	21,65,869	4,31,182	2,88,538

स्रोत: आरबीआई

¹² "2025 तक भारत में डिजिटल भुगतान बाजार 3 गुना बढ़कर ₹7,092 ट्रिलियन होने की संभावना : रिपोर्ट", इकोनॉमिक टाइम्स, 23 अगस्त, 2020

दो महीने पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से खुदरा क्षेत्र में लेन-देन और मूल्य की मात्रा में क्रमशः 10.3 प्रतिशत और 12.3 प्रतिशत तेजी का अनुमान है। तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के माध्यम से मात्रा और मूल्य में लेन-देन में पिछले महीने दर्ज की गई 38.7 और 38.6 प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 33.5 प्रतिशत और 33.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर 2020 तक 6 प्रतिशत अंक की छलांग के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन की मात्रा में 76.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मूल्य वृद्धि दर 99.4 प्रतिशत पर स्थिर रही। इस समय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की संभावना को देखते हुए और नवाचार, सुलभता और ग्राहक सुविधा को मजबूत करने और उसे बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा हाल ही में यूपीआई पर थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (टीपीएपी) पर किए गए लेन-देन पर मात्रा कैप लागू की गई है।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से बिल भुगतान में तेजी आई, जिसमें मात्रा में 84 प्रतिशत (पिछले महीने 86.2 प्रतिशत) और मूल्य में 106 प्रतिशत (पिछले महीने 97.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सिस्टम पर ऑनबोर्डिंग द्वारा डिजिटल मोड और बिलर्स के तेजी से प्रतिसाद के कारण उपभोक्ता संबंध में वृद्धि होने से बीबीपीएस गतिविधि सीमित की गयी है।

अग्रानुक्रम में आर्थिक पुनरुद्धार गति को दर्शाते हुए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) के वृद्धि में पिछले महीने में क्रमशः मात्रा में 60.4 प्रतिशत और मूल्य में 115.2 प्रतिशत और 83.3 प्रतिशत के शीर्ष पर 48.1 प्रतिशत का क्रमिक सुधार देखा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत निधियों के वितरण के कारण आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एडपीएस) और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के टर्नओवर से ग्रामीण इलाकों से मांग में वृद्धि का पता चलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस योजना के तहत त्रैमासिक किशतों के रूप में लाभार्थी किसानों के खातों में धन के संवितरण के आधार पर 2020 के अप्रैल, अगस्त और दिसंबर के महीनों में एनएसीएच वृद्धि में तेजी आई। इन ऋण-व्यवस्थाओं की मिररिंग करते हुए इन महीनों में एडपीएस के माध्यम से या उसके

तुरंत बाद नकद निकासी में जनवरी 2021 में मात्रा में 89.1 प्रतिशत और मूल्य में 92.3 प्रतिशत अपटिक्स (पूर्ववर्ती लेनदेन की कीमत से अधिक मूल्य पर शेयर बाजार में एक लेनदेन) देखा गया। त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड, एडपीएस और ऑफलाइन जैसे भुगतान विकल्पों के आने से, ग्रामीण भारत निकट भविष्य में डिजिटल भुगतानों का नतिपरिवर्तन बिंदु बन सकता है, जिसके लिए रिजर्व बैंक डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सक्षम नीति वातावरण प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

जनवरी 2021 का महीना भी नियामक मोर्चे पर महत्वपूर्ण कार्यों से भरा हुआ था। कुछ अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप द्वारा अपनाई जा रही अनुचित उधार प्रथाओं का संज्ञान लेते हुए रिजर्व बैंक ने वित्तीय नवाचार और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए एक उचित नियामक दृष्टिकोण की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु विनियमित और अनियमित वित्तीय संस्थाओं के बीच डिजिटल ऋण गतिविधियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। फरवरी में, रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं के लिए न्यूनतम मानकों को लागू करते हुए "डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निर्देश" जारी किया है। एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में, चेक-आधारित लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चेक के लिए पोजेटिव पे सिस्टम 1 जनवरी 2021 से शुरू हो गई है। डिजिटल इंडिया के विज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में काम करते हुए, रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी, अपने भुगतान अवसंरचना विकास निधि का संचालन किया है, जिसका उद्देश्य टियर III से VI केंद्रों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना को बढ़ाना है। त्वरित शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक 24X7 डिजिटल भुगतान हेल्पलाइन स्थापित करेगा और वर्तमान के तीन लोकपाल सुविधाओं को एक में एकीकृत करने के लिए "वन नेशन, वन लोकपाल" योजना शुरू करेगा। इनोवेशन स्पेस से 'खुदरा भुगतान' के साथ विनियामक सैंडबॉक्स के दल और 'सीमा पार से भुगतान' के साथ दूसरे दल की घोषणा' विषय के साथ का पहला परीक्षण चरण की शुरुआत का समाचार प्राप्त हो

रहा है। महामारी के दौरान संपर्क रहित भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से ₹2,000 से ₹5,000 तक कार्ड (और यूपीआई) के माध्यम से आवर्ती लेनदेन के लिए संपर्क रहित कार्ड लेनदेन और ई-जनादेश की सीमा बढ़ा दी है।

निष्कर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखने का नजरिया अचानक से आए वायरस के नए, तेज संचारी योग्य स्ट्रेन से घिरा हुआ है, जिसके खिलाफ वैक्सीन निर्माताओं को तेजी से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। यह इस संदर्भ में है कि विश्व स्तर पर टीकों का फैलाव के लिए एक अच्छी समन्वित और तेज रणनीति की अबिलंब आवश्यकता है। भारत, कुछ अन्य देशों की तरह, तेजी से फैलाव कार्यक्रम शुरू किया जिसमें पहले से ही 20 से अधिक देशों को अनुदान और वाणिज्यिक आपूर्ति के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में कुछ राज्यों में संक्रमण में वृद्धि और एक भारतीय उत्परिवर्तन के अलगाव के बावजूद अधिक आपूर्ति और अधिक टीके पाइपलाइन में हैं। हालांकि संतुलन पर, काफी अनिश्चितता ने हमारे आउटलुक को चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन इसके रिकवरी की शक्ति और इसके व्यापक दायरे आशावाद और जीवित रहने और संभलने की जिजीविषा रखती है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 26 फरवरी को जारी किए गए राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमानों – तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी ने पहली छमाही के संकुचन को हटा दिया है और सकारात्मक क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया - को इस लेख ने पुष्टि की है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2020-21 का खाद्यान्न उत्पादन 303 मिलियन टन रखा गया, जोकि अब तक की सभी प्रमुख फसलों और रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए है। इस मंदी से उभरने के साथ कारोबार फिर से खुलने और उपभोक्ताओं का कार्यालयों और दुकानों में वापस आने से भारतीय अर्थव्यवस्था ने मुसीबत के दिन पार कर लिया है। ये सभी मुद्रास्फीति सकारात्मक गतिविधियां हैं। एक साल पहले की तुलना में दालों का उत्पादन 6 प्रतिशत अधिक है, खाद्यान्न के क्षेत्र में मुद्रास्फीति कम निर्धारित की गई है, लेकिन मूल मुद्रास्फीति की कमी पर ध्यान देने की

आवश्यकता है। जबकि पेट्रोलियम उत्पादों पर अत्यधिक उच्च उत्पाद शुल्क सार्वजनिक वित्त की स्थिति के लिए मुसीबत बनी हुई है, लेकिन राजस्व के अन्य प्रमुखों में उछाल इस स्ट्रगल को ढीला कर सकता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैस की पंप कीमतों को और अधिक तुलनीय स्तर पर ला सकता है, मुद्रास्फीति दृष्टिकोण में सुधार और उपभोक्ता कल्याण का विस्तार कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण से भी, भारत के लिए महंगाई की स्थिति से उबरना महत्वपूर्ण है और उत्पादकता और दक्षता के लाभ को पुनः प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को पुनः तैयार करे और संरचनात्मक सुधार करे।

वर्ष 2020-21 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थितियों का विकास करीब आ रहा है और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हमारे लिए एक चुनौती खड़ा करेगी। राजकोषीय नीति अधिकारियों को अर्थव्यवस्था को उभारने में आनेवाले मुसीबत और स्थायी वित्त सुनिश्चित करने की लठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मौद्रिक अधिकारियों को अभी भी बढ़े हुए ऋण की आवश्यकता के समक्ष ब्याज दर संरचना के क्रमबद्ध विकास के लिए समझौतापारक और वसूली का समर्थन करना पड़ता है। जबकि नीति अधिकारी अपनी प्रतिबद्धता का पूर्णता से प्रदर्शन कर रहे हैं, बाजार अनिश्चितता का शिकार हो रहे हैं और रिटर्न के लिए छिटपुट बदलाव कर सुरक्षित स्थान की ओर लौट रहे हैं। एक साझा समझदारी और सामान्य अपेक्षाएं इस हलचल में सहारा दे सकता है। बाजार और संस्थानों को कार्यशील बनाए रखने के लिए, उधार लेने और लागत को आसान बनाने में; वित्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए अधिकारियों के ट्रैक रिकॉर्ड पर - वास्तव में बहुत कम निर्भर करना है- निर्भर रहना पड़ता है। प्रतिफल वक्र का एक क्रमिक विकास सभी कार्य करता है। उभरती अर्थव्यवस्था के कारण सभी लोग उससे लाभ प्राप्त करेंगे और बाजार तरक्की पाने के लिए संघर्ष कर रहे नीति अधिकारियों को समर्थन देने से बेहतर कोई कार्य नहीं कर सकते।

आज इसमें थोड़ा संदेह है कि खपत की बहाली पर आधारित वसूली चल रही है। इस तरह की उथले और अल्पकालिक वसूली की ओर निर्णायकों का ध्यान जा रहा है। निवेश के लिए रूचि बढ़ाने में तेजी लाना महत्वपूर्ण है, जिंदादिली को जागृत करना ना कि निष्क्रियता के बजाय कार्रवाई के लिए एक सहज आग्रह, और

मात्रात्मक संभावनाओं से गुणित मात्रात्मक लाभों के भारत औसत के परिणाम के रूप में ¹³ कुल मांग के सभी इंजनों को चालू किया जा रहा है; केवल निजी निवेश कार्यशील नहीं है। यह समय निजी निवेश के क्रियाशील रहने के लिए उपयुक्त है। राजकोषीय

नीति, अब तक के सबसे बड़े कैपेक्स बजट और बेहतर व्यवसाय करने पर जोर देते हुए, इसमें निजी निवेश का अंतर्गमन की पेशकश की है। क्या भारतीय उद्योग और उद्यमिता मिलकर इसका लाभ उठाएंगे?

¹³ जॉन मेनार्ड कीन्स द जनरल थ्योरी ऑफ एंप्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936